राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण मंगलवार 09 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-282 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

इंडिगो संकट- 7वें दिन 500+ फ्लाइट कैंसिल

■ इंडिगो की बेंगलुरु-वडोदरा फ्लाइट में कबूतर घुसा

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकीं हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थीं। इंडिगो के उएड पीटर एल्बर्स ने कहा- हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो संकट उसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण हुआ। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हुईं। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। जांच जारी है। हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बने। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें इंडिगो की फ्लाइट के अंदर कबूतर उड़ता दिखाई दे रहा है। ये फ्लाइट बेंगलुरु से वडोदरा जा रही थी। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। उखक सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है।

आरपीएसएफ जवानों को तोहफा: दिल्ली में बनेगा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

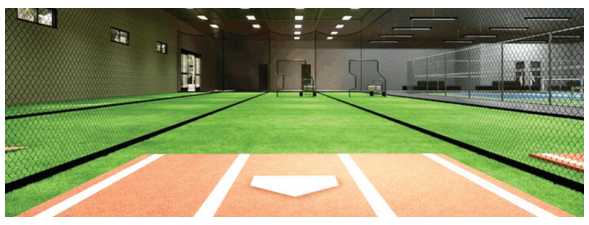

एजेंसी

नई दिल्ली। रेलवे की महत्वपूर्ण सुरक्षा इकाई रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (आरपीएसएफ) के जवानों के स्वास्थ्य, फिटनेस और प्रशिक्षण स्तर को और बेहतर बनाने के लिए जल्द ही दिल्ली में एक अत्याधुनिक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू होने जा रहा है। यह सुविधा दयाबस्ती स्थित आरपीएसएफ की 6वीं बटालियन में विकसित की जाएगी। दयाबस्ती दिल्ली का घना आबादी वाला रेलवे कॉलोनी क्षेत्र है। यहां हजारों रेलकर्मी और उनके परिवार रहते हैं। यहां कोई बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या ऑडिटोरियम नहीं था। अब नई सुविधा से 6वीं बटालियन के जवानों के साथ ही आसपास की अन्य बटालियनों के जवान और रेलवे कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। इनके निर्माण का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। 2.10 करोड़ की अनुमानित लागत से 8 महीनों पूरा होगा प्रोजेक्ट : प्रोजेक्ट पर करीब 2.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी और इसे आठ महीनों की समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य है। आरपीएसएफ देश के रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती है।

भारतीयों के साथ तमीज से रहो...चीन को विदेश मंत्रालय ने अलग अंदाज में समझा दिया, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को चीन से 'आश्वासन' माँगा कि चीनी हवाई अड्डों से गुज़रने वाले भारतीय नागरिकों को ÷चुनिंदा निशाना नहीं बनाया जाएगा, मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाएगा या परेशान नहीं किया जाएगा÷ और बीजिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले नियमों का सम्मान करेगा। साप्ताहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक यात्रा परामर्श भी जारी किया जिसमें चीन की यात्रा करने वाले या वहाँ से गुज़रने वाले भारतीयों को उचित विवेक का प्रयोग करने की चेतावनी दी गई। जायसवाल मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि विदेश मंत्रालय चीन जाने वाले या वहां से होकर जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए क्या सिफारिश करता है। पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला पेमा वांगजोम थोंगडोक को शंघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे तक रोके रखा गया था। चीनी अधिकारियों ने दावा किया था कि उनका भारतीय पासपोर्ट अवैध है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है।

शंघाई हवाई अड्डे पर हुई हालिया घटना, जिसका आपने ज़क्रि किया है, के बाद हम आपकी चिंता से पूरी तरह सहमत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीनी अधिकारी यह आश्वासन देंगे कि चीनी हवाई अड्डों से गुज़रने वाले भारतीय नागरिकों को चुनिंदा तौर पर निशाना नहीं बनाया जाएगा, मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाएगा या परेशान नहीं किया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले नियमों का चीनी पक्ष द्वारा सम्मान किया जाएगा। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को चीन की यात्रा करते या वहाँ से गुज़रते समय उचित विवेक का प्रयोग करने की सलाह देगा। थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं और शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रुकी थीं। तभी चीनी आव्रजन अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया और उनकी राष्ट्रीयता का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है।

इस घटना के बाद, भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया और कहा कि यह पूर्वोत्तर राज्य ÷भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग÷ है। साथ ही, भारत ने यह भी कहा कि बीजिंग की ओर से किसी भी तरह का इनकार इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदल सकता। जायसवाल ने पिछले महीने एक अलग प्रेस वार्ता में थोंगडोक से जुड़ी घटना पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया था और हिरासत को 'मनमाना' बताया था। उन्होंने इस मामले पर भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार ने घटना के तुरंत बाद बीजिंग और नई दिल्ली, दोनों जगहों पर चीन को कड़ा विरोध पत्र जारी किया था।

पीएम मोदी बोले: कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए

60 मिनट के भाषण में 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र

एजेंसी

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने एक घंटे की स्पीच में कहा, 'वंदे मातरम् अंग्रेजों को करारा जवाब था, ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। पीएम ने कहा, उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। फिर पिछले दशकों में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। वंदे मातरम् के साथ विश्वासघात क्यों हुआ। वो कौन सी ताकत थी, जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी। पीएम मोदी ने एक घंटे की स्पीच में वंदे मातरम् 121 बार, देश 50, भारत 35, अंग्रेज 34, बंगाल 17, कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। उन्होंने वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार, नेहरू 7 बार, महात्मा

गांधी 6 बार, मुस्लिम लीग 5 बार, जिन्ना 3 बार, संविधान 3 बार, मुसलमान 2 बार, तुष्टिकरण 3 बार कहा। मोदी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम् के खिलाफ नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। PM ने कहा कि बजाय इसके कि नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जबाब देते, उसकी निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने वंदे मातरम् की ही पड़ताल शुरू कर दी। वंदे मातरम् का स्मरण इस सदन का सौभाग्यः 'जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश के आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम् का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है।' वंदे मातरम् के 150 साल पर भारत तेजी से बढ़ रहाः जब वंदे मातरम् के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए, तब देश आपातकाल के अंधेरे में था। आज जब इसके 150 वर्ष हो रहे हैं, तो भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1906 का एक किस्सा सुनायाः वंदे मातरम् से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए कहा- 20 मई 1906 को बारीसाल (अब बांग्लादेश में है) में वंदे मातरम् जुलूस निकाला, जिसमें 10 हजार से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे। इसमें हिंदू और मुस्लिम समेत सभी धर्म और जातियों के लोगों ने वंदे मातरम् के झंडे हाथ में लेकर सड़कों पर मार्च किया था। बंगाल के लिए वंदे मातरम् गली-गली का नारा बन गयाः हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम् कहते थे। हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम् कहते हुए फांसी को चूम लिया। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम् गली-गली का नारा बन गया था और यही नारा बंगाल को प्रेरणा देता था।

सरसावा एयरपोर्ट पर अखिलेश की साइड मीटिंग

■ सियासत गरमाई

एजेंसी

सहारनपुर। जनपद के सरसावा एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व विधायक मनोज चौधरी के बीच हुई 'साइड मीटिंग' ने राजनीतिक चचाओं को तेज कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मनोज चौधरी, एयरपोर्ट पहुंचते ही अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उन्हें किनारे ले जाते हैं और कुछ देर तक धीमी आवाज में बातचीत करते दिखाई देते हैं।रविवार को अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तीन अलग-अलग शादियों में पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसी कार्यक्रम से लौटते समय एयरपोर्ट पर यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जो वायरल होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। वायरल वीडियो में अखिलेश यादव से हाथ पकड़कर बातचीत करने वाले व्यक्ति को सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र से जुड़े पूर्व विधायक मनोज चौधरी बताया जा रहा है। एयरपोर्ट पर हुई यह निजी बातचीत किस मुद्दे पर हुई। इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इसे भविष्य की संभावित रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो पर चर्चा बढ़ने के बावजूद न तो समाजवादी पार्टी और न ही मनोज चौधरी की ओर से कोई टिप्पणी की गई है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।

क्लब के मालिक का हादसे के बाद पहला बयान

■ लिखा- लोगों की मौत से हिल गया हूं, घटना के बाद से ही फरार

एजेंसी

गोवा। रविवार रात गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग और उसमें 25 लोगों की मौत पर अब नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा का पहला बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हादसे में लोगों की मौत के बाद से वह हिल गया है। गौरतलब है कि सौरभ हादसे के बाद से ही फरार है। गोवा पुलिस की एक टीम रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हुई, ताकि क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तलाश की जा सके, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बीच सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया पर

साझा एक पोस्ट में लिखा, 'नाइट क्लब प्रबंधन इस त्रासदी पर दुखी है और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रबंधन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हरसंभव कदम उठाएगा।' सौरभ लूथरा की लिंक्डइन प्रोफाइल में उसे 'चैयरमैन एट रोमियो लेन, बिर्क' लिखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सौरभ लूथरा कम ही गोवा में दिखाई देता है और विभिन्न कानूनी मामलों में भी वह अपनी जगह अपने प्रतिनिधियों को ही भेजता है। क्लब के स्टाफ ने भी बताया कि क्लब का मालिक कम ही दिखाई देता है और वह एक महीने में एक बार ही नाइटक्लब आता है और कर्मचारियों से भी बेहद कम बात करता है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में पुलिस ने क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक (49 वर्षीय, निवासी आर.के. पुरम, नई दिल्ली), महाप्रबंधक विवेक सिंह (27 वर्षीय, निवासी जौनपुर, उत्तर प्रदेश), बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया (32 वर्षीय, निवासी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) और गेट प्रबंधक प्रियांशु ठाकुर (32 वर्षीय, निवासी मालवीय नगर, नई दिल्ली) को गिरफ्तार किया है।

मलयालम एक्टर दिलीप एक्ट्रेस से उत्पीड़न मामले में बरी

एजेंसी

कोच्चि। केरल के एनार्कुलम सेशन कोर्ट ने सोमवार को 2017 में साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस से गैंगरेप मामले में मलयालम एक्टर दिलीप को बरी कर दिया। जज हनी एम. वर्गीस ने कहा कि दिलीप एक्ट्रेस से उत्पीड़न मामले में शामिल नहीं थे। दिलीप के साथ तीन अन्य आरोपियों को भी अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुनील एन.एस. उर्फ. पल्सर सुनी सहित छह आरोपियों को दोषी ठहराया। इन पर घटना को अंजाम देने का आरोप था। कोर्ट 12 दिसंबर को दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाएगी। दिलीप ने कोर्ट से बाहर

आने के बाद मीडिया से कहा- मेरी छवि और करियर खत्म करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। एक्टर ने किसी का नाम लिए बिना कहा- एक सीनियर महिला पुलिस अधिकारी और उसके चुने गए कुछ गुंडे पुलिसवालों के एक ग्रुप ने मुझे फंसाया। यह मामला मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली एक एक्ट्रेस से जुड़ा है। 17 फरवरी, 2017 की रात को कुछ लोगों ने उसकी कार में जबरन घुसकर उसका अपहरण कर लिया।

बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला

नोट गिनने की मशीन बुलाई, 93 लाख रुपये ऑनलाइन मिले, बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रखी थी

एजेंसी

मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। अब इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का एक वीडियो सामने आया है। हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को घोषणा की कि वह फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करवाएंगे। इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। हुमायूं ने कहा कि वे जल्द ही एक नई पार्टी बनाएंगे जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। वे 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वे ओवैसी की पार्टी के संपर्क में हैं और अलायंस कर सकते हैं। 28 नवंबरः मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में

कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर नजर आए। लिखा था- 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। बीजेपी ने इसका विरोध किया, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन किया। 3 दिसंबरः TMC ने मामले से खुद को अलग किया। बयान में कहा कि- कबीर की इस घोषणा से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। एक और पार्टी नेता ने कहा- हुमायूं कबीर ने यह विवाद इसलिए खड़ा किया है ताकी उन्हें रेटनगर सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सके। हुमायूं वर्तमान में मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक हैं। 4 दिसंबरः मामला बढ़ता देखा TMC ने विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने कहा- पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। पार्टी एक्शन पर हुमायूं ने कहा- मैं अपने बाबरी मस्जिद वाले बयान पर कायम हूं। 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की भी घोषणा करूंगा। विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं उन दोनों (TMC और भाजपा) के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर मीडिया से बात करते हुए 28 नवंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, जो कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वे अपने साथ 500 लोगों को ले जाएंगे। हुमायूं कबीर पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के समय मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में हुमायूं कबीर ने एक जनसभा में कहा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर दो घंटे में तुम्हें (हिंदुओं को) भागीरथी नदी में डुबो न दिया। तुम 30% हो, हम 70% (मुस्लिम) हैं।

आरोपी शाहीन-मुजम्मिल समेत चार की कोर्ट में पेशी

एनआईए की कस्टडी चार दिन और बढ़ी

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजंसी ने दिल्ली आतंकी मामले से जुड़े चार आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। जहां डॉ. मुजम्मिल, डॉ. आदिल, मुफ्ती इरफान और डॉ. शाहीन सईद की एनआईए हिरासत को चार दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

इन सभी आरोपियों को सोमवार को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था।यह मामला दिल्ली में हुए एक बड़े आतंकी हमले से संबंधित है, जिसकी जांच एनआईए द्वारा की जा रही है। हाल ही में, जांच एजेंसी ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की थीं, जिनमें ये चारों आरोपी शामिल हैं। कोर्ट ने प्रारंभिक जांच के आधार पर इन आरोपियों को एनआईए की हिरासत में भेजा था, ताकि उनसे पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचा जा सके। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष अदालत ने आरोपी सोएब की हिरासत को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट में बीते शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सोएब को अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आंजू बजाज चंदना ने पूर्व 10-दिवसीय रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद यह

फैसला सुनाया था। यह कार्यवाही एक बंद अदालत कक्ष में संपन्न हुई था।

एनआईए के अनुसार, सोएब पर 10 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले से ठीक पहले बम बनाने वाले उमर उन नबी को शरण देने का आरोप है। जो फरीदाबाद का निवासी है। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाला सातवां व्यक्ति है। यह हमला राजधानी में हाल के वर्षों में हुए सबसे गंभीर आतंकवादी हमलों में से एक था, जिसमें एक चलती हुई हुंडई आई20 कार में हुए विस्फोट में कई लोगों की जान गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। एनआईए ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी ने न केवल उमर उन नबी को शरण दी, बल्कि हमले से पहले आतंकवादी की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रदान किया। यह गिरफ्तारी उमर से जुड़े छह प्रमुख सहयोगियों की पहले की गिरफ्तारी के बाद हुई है, जिन्हें जांच के दौरान पकड़ा गया था। एनआईए का मानना है कि इस नई गिरफ्तारी से एजेंसी की बमबारी के पीछे के ऑपरेशनल नेटवर्क की समझ मजबूत हुई है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025

राजस्व,स्वास्थ्य -नीति,राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्यों पर प्रभाव-एक विस्तृत विश्लेषण

(लेखक - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी/ईएमएस)

वैश्विक स्तरपर भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच गहरा अंतर्संबंध है।लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि तंबाकू, सिगरेट,शराब और अन्य नशे के उत्पाद देश के स्वास्थ्य ढाँचे पर बोझ डालते हैं और इसके कारण सरकारों को स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है।इसी परिप्रेक्ष्य में 5दिसंबर 2025 को लोकसभा ने हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल,2025 को मंजूरी दी,जिसने राजनीतिक हलकों स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राज्यों के बीच एक गहरा विमर्श खड़ा कर दिया।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह विधेयक न केवलस्वास्थ्य सुरक्षा पर अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कोशिश है,बल्कि यह इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि नशे और स्वास्थ्य संबंधी संकट अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उन वस्तुओं पर अतिरिक्त सेस लगाना है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी ,पान मसाला गुटखा, शराब और अत्यधिक चीनी वाले पेय। इन उत्पादों के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ वर्षों से बढ़ता जा रहा है और इससे स्वास्थ्य ढाँचा पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक केवल राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाया गया है ताकि महामारी, बायो- सिक्योरिटी जोखिम और गैर- संचारी रोगों के बढ़ते खतरे का मुकाबला किया जा सके। सरकार का तर्क है कि कोविड -19 ने साफ कर दिया कि स्वास्थ्य संकट किसी भी समय राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में बदल सकता है,इसलिए स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को एकीकृत दृष्टिकोण सेदेखना आवश्यक है। विपक्ष का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य की आड़ में राजस्व बढ़ाना चाहती है और तंबाकू कंपनियों के सेलिब्रिटी विज्ञापन पर रोक न लगाना इस नीति की मंशा पर सवाल खड़ा करता है।विपक्ष ने लोकसभा में यह भी पूछा कि जब सरकार पान मसाला और सिगरेट पर सेस बढ़ाकर कीमतें महंगी कर रही है तो फिर इन उत्पादों का विज्ञापन अभिनेता और क्रिकेटर क्यों कर रहे हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि विज्ञापन संबंधी नए नियम तैयार किए जा रहे हैं और इन उत्पादों के प्रचार पर कठोर प्रतिबंध लगाने पर विचार चल रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि कीमतें बढ़ाने का उद्देश्य केवल राजस्व नहीं, बल्कि खपत में कमी लाना है,क्योंकि विश्व स्वास्थ्यसंगठन और विश्व बैंक के कई अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ है कि तंबाकू और शराब पर कर बढ़ाने से सेवन में उल्लेखनीय गिरावट आती है, विशेषकर युवा वर्ग के बीच। वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि सेस का उद्देश्य लोगों को इन हानिकारक वस्तुओं से दूर रखना है, क्योंकि जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, खपत स्वाभाविक रूप से घटती है और इसका सकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव सीधे समाज पर पड़ता है।

साथियों बात अगर हम इस बिल के मुख्य प्रावधानों की करें तो, बिल के प्रमुख प्रावधान,क्या है 'हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025'?इस विधेयक का मूलउद्देश्य स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अतिरिक्त कराधान के माध्यम से एक विशेष कोष तैयार करना है। इसमें उन उत्पादों पर सेस लगाने का प्रस्ताव है जो स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक माने जाते हैं,जैसे-(1) सिगरेट और बीड़ी (2) पान मसाला और गुटखा (3) बिना धुएँ वाला तंबाकू (4) शराब (कुछ उच्च श्रेणी उत्पादों सहित) (5) शीतल पेय जिनमें अत्यधिक चीनी हो (6) वे वस्तुएँ जिनका सेवन गैर-संचारी रोगों को बढ़ाता हैसरकार का प्राथमिक दावा है कि यह सेस किसी सामान्य राजस्व के लिए नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य अवसंरचना, राष्ट्रीय चिकित्सा आपातकाल प्रणाली, महामारी-तैयारी और सीमाई क्षेत्रों की मेडिकल- सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। कोविड-19 के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि स्वास्थ्य संकट तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षासंकट में बदल सकता है; इसलिए इस विधेयक में स्वास्थ्य और सुरक्षा को एकीकृत वित्तीय दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की गई है।सेस की राशि सीधे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हेल्थ एंड सिक्योरिटी फंड में जमा होगी।इससे जुड़े प्रावधानों में शामिल है (1) राज्यों को उनके स्वास्थ्य खर्च के अनुपात के आधार पर अनुदान (2) राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए मेडिकल प्रावधान (3) महामारी- निगरानी और बायो-सिक्योरिटी संरचना को मजबूत करना (4) कैंसर एनसीडी और तंबाकू-जनित रोगों के लिए विशेष कार्यक्रम

साथियों बात अगर हम कोविड- 19 के दौरान देश ने क्या देखा इसको समझने की करें तो शराब और सिगरेट जैसी वस्तुएँ पाँच से दस गुना ऊँची कीमत पर भी बिक रही थीं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इन वस्तुओं की लत मांग को कृत्रिम रूप से ऊँचा बनाए रखती है, लेकिन साथ ही यह भी पाया गया कि कीमतें बढ़ने से नए उपभोक्ता इनसे दूर रहते हैं। महामारी के अनुभव ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया कि नशे की वस्तुओं की बिक्री को नियंत्रित करना और उनकी खपत को कम करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। इसीलिए इस विधेयक के माध्यम से सरकार केवल कराधान ही नहीं,बल्कि निगरानी प्रणाली मजबूत करने, अवैध तंबाकू और शराब की आपूर्ति रोकने, स्वास्थ्य शिक्षा बढ़ाने और नशामुक्ति कार्यक्रमों का विस्तार करने पर भी जोर दे रही है।

साथियों बात अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्थिति को समझने की करें तो हर वर्ष विश्वभर में लगभग 80 लाख लोग धूम्रपान के कारण समय से पहले मरते हैं और इनमें से 10 लाख लोग वे होते हैं जो स्वयं धूम्रपान नहीं करते, बल्कि दूसरों के धुएँ का शिकार बनते हैं। भारत में स्थिति और भी गंभीर है, जहाँ हर वर्ष धूम्रपान से 10 लाख और अन्य तंबाकू उत्पादों के कारण कुल मिलाकर लगभग 13.5 लाख मौतें दर्ज की जाती हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि भारत एक ऐसी स्थिति में है जहाँ तंबाकू किसी महामारी की तरह फैल चुका है और इसके विरुद्ध कठोर नीतियाँ आवश्यक हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक अध्ययन के अनुसार,एक सिगरेट पीने से जीवन के लगभग 20 मिनट कम हो जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति दस वर्षों तक प्रतिदिन दस सिगरेट पीता है तो उसकी जीवन प्रत्याशा लगभग 500 दिन कम हो जाती है। यह अध्ययन दर्शाता है कि तंबाकू केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन को तेज़ी से समाप्त करने वालाजोखिम है और इससे देश की कार्य-क्षमता, उत्पादकता और आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

साथियों बातें कर हम अब यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या यह विधेयक केवल पैसा जुटाने का साधन है इसको समझने की करें, तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है।इस बिल में दोहरे उद्देश्य सम्मिलित हैं,एक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, और दूसरा तंबाकू और नशे की वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित कर लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना।

सरकार ने तंबाकू-निषेध कार्यक्रमों, स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान, सामाजिक मीडिया पर स्वास्थ्य चेतावनियों, सेलिब्रिटी विज्ञापन पर नियंत्रण, अवैध सप्लाई चेन पर कठोर दंड और नशामुक्ति केंद्रों का विस्तार करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही तंबाकू उगाने वाले किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रेरित करने का प्रावधान भी किया जा रहा है ताकि आर्थिक रूप से वे प्रभावित न हों।चूँकि तंबाकू और शराब से संबंधित कई कर व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि राज्यों पर इस बिल का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति को नुकसान न हो, इसके लिए कम्पेन्सेशन ग्रांट का प्रावधान किया गया है। इस कानून से राज्यों के स्वास्थ्य बजट को भी लाभ होगा क्योंकि केंद्रीय हेल्थ एंड सिक्योरिटी फंड से राज्यों को उनकी ज़रूरत और स्वास्थ्य सूचकांकों के आधार पर धन उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी अपेक्षित है कि केंद्र और राज्यों के बीच अवैध शराब, नकली तंबाकू, स्वास्थ्य कार्यक्रम और रोकथाम तंत्र को लेकर बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथियों बातें कर हम विश्व में नशा मुक्ति वातावरण उत्पन्न करने की करें तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशे जैसे तंबाकू, शराब, ड्रग्स, सुंघनी, ई-सिगरेट, निकोटिन पाउच तथा अन्य व्यसनी पदार्थ आज समाज में गहरी जड़ें जमा चुके हैं। इन पर रोक लगाने के लिए सरकारें अनेक कड़े कानून, दंड और प्रतिबंध लागू करती रही हैं, परंतु केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता। नशे की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे मिलीभगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी गहराई से जुड़ी होती है, जिसके कारण कठोर दंडात्मक प्रावधान कई बार वास्तविक बदलाव लाने में पर्याप्त नहीं होते।इसके विपरीत जनजागरूकता एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो व्यक्ति की सोच और व्यवहार को मूल स्तर पर प्रभावित करती है। जब जनता को यह समझाया जाए कि नशा केवल शरीर ही नहीं, परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है, तब वह स्वयं नशे से दूर रहने का निर्णय ले पाती है। विद्यालयों, महाविद्यालयों कार्यस्थलों, पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा परामर्श, सोशल मीडिया के माध्यम से सही जानकारी, और नशामुक्ति केंद्रों की भूमिका,ये सभी उपाय कानून से कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।इसलिए नशे को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जनजागरण, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा और युवाओं के लिए सकारात्मक विकल्प उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यही वह संतुलित रणनीति है जो समाज को नशामुक्त और स्वस्थ बना सकती है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 केवल एक कराधान नीति नहीं,यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है।

साथियों बातें कर हम अब यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या यह विधेयक केवल पैसा जुटाने का साधन है इसको समझने की करें, तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है।इस बिल में दोहरे उद्देश्य सम्मिलित हैं,एक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, और दूसरा तंबाकू और नशे की वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित कर लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना।

संपादकीय

डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता

यह विडंबना है कि जब तक देश में कथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अनुमानित तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक ठगी की जा चुकी है, कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी मुहिम शुरू हो पा रही है। वह भी सरकार के बजाय शीर्ष अदालत की पहल पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करे, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर की सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है। दुखद है कि साइबर अरेस्ट के मामलों में सबसे अधिक निशाना बुजुर्गों को ही बनाया जाता है, जिन्हें डिजिटल लेन-देन की गंभीर जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों को निशाना बनाने का यह प्रतिशत 78 से 82 फीसदी बताया जाता है। कई जगह यह प्रतिशत 99 फीसदी तक है। वहीं जनवरी से अप्रैल 2024 में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के 46 फीसदी मामलों के तार म्यांमार,कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़े रहे हैं। निस्संदेह, हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध के सबसे कुटिल रूप में बनकर उभरी है। यह अपराध न केवल देश की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये, बल्कि कानून प्रवर्तन तंत्र में जनता के विश्वास के लिये भी बड़ा खतरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन घोटालों की देशव्यापी जांच सीबीआई को सौंपने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समय के अनुरूप सार्थक हस्तक्षेप है। इसी क्रम में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिये सीबीआई को सहमति दें। दरअसल, न्यायालय ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि साइबर अपराधी राज्यों की सीमाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर टुकड़ों-टुकड़ों में जांच सीमा-पार के साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बढ़ावा देती है। दरअसल, साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिये भोले-भाले लोगों व बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। वे कानून प्रवर्तन अधिकारी या जज बनकर मोटी रकम देने के लिये उन्हें आतंकित करते हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति से एक करोड़ रुपये की ठगी के बाद अदालत ने इस व्यापक समस्या का स्वत- संज्ञान लिया। उन्हें धमकाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेशों का इस्तेमाल किया गया। यह बेहद परेशान करने वाली स्थिति है कि साइबर अपराधी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल रहे हैं। तभी शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है, देश की केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की तह तक तुरंत पहुंचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों को फीज करने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग को भी सिम कार्ड के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिये कहा गया है। निश्चित रूप से कोर्ट की सार्थक पहल के बाद यदि ये सभी उपाय सिरे चढ़ते हैं तो इस गंभीर अपराध के खिलाफ एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दे पाना संभव होगा। कोर्ट ने विश्वास जताया है कि केंद्रीय एजेंसी बिना किसी भय या पक्षपात के जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी।

भ्रष्टाचार मुक्त भारतः स्वयं से सुधार का संकल्प

(लेखक - डॉ.राघवेंद्र शर्मा)

9 दिसंबर-अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर विशेष)

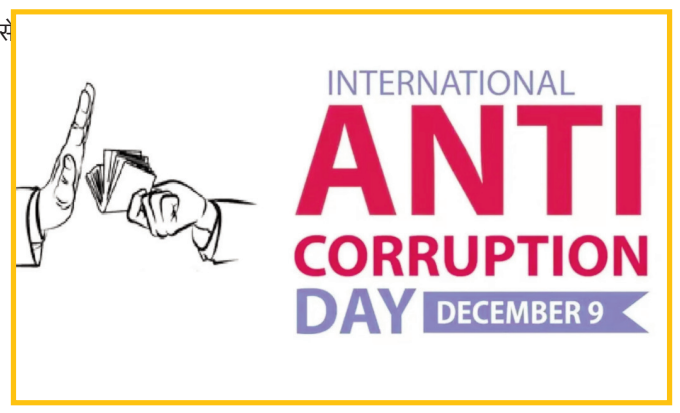

भ्रष्टाचार किसी भी राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा और समाज की जड़ों को खोखला करने वाली एक लाइलाज बीमारी के समान है। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि सामूहिक नागरिक चेतना से ही संभव है। इस वर्ष का यह दिवस न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का प्रतीक है, बल्कि भारत के संदर्भ में यह आत्म-मंथन का भी समय है कि हमने इस सामाजिक बुराई से निपटने में कितनी दूरी तय की है और अभी कितनी राह बाकी है।

भारतीय राजनीति और प्रशासन के इतिहास में एक दौर वह भी था, जब भ्रष्टाचार को व्यवस्था का हिस्सा मान लिया गया था। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार जब दिल्ली से 1 रुपया भेजती है, तो गरीब की जेब तक केवल 15 पैसे ही पहुँचते हैं। वह 85 पैसों का लीकेज बिचौलियों, भ्रष्ट अधिकारियों और पारदर्शी तंत्र के अभाव की भेंट चढ़ जाता था। यह केवल आर्थिक हानि नहीं थी, बल्कि करोड़ों देशवासियों के भरोसे की हत्या थी। संसाधनों का यह असमान वितरण और संस्थागत भ्रष्टाचार ही वह कारण था, जिसने दशकों तक भारत के विकास की गति को थामे रखा।

वर्तमान परिदृश्य में, विशेषकर पिछले दशक में, भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध तकनीकी प्रहार किया है। मोदी सरकार की वर्तमान कार्य प्रणाली और डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन में अभूतपूर्व पारदर्शिता का संचार किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की नीति ने उन बिचौलियों को व्यवस्था से बाहर कर दिया है जो गरीबों का हक मारते थे। आज जब केंद्र से पैसा चलता है, तो वह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में बिना किसी कटौती के पहुँचता है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कुछ प्रमुख कारकों ने बड़ी भूमिका निभाई है। सरकारी से का डिजिटलीकरण होने से मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है, जिससे सुविधा शुल्क या रिश्वत की गुंजाइश घटी है। जीएसटी जैसी एकीकृत कर प्रणाली ने कर चोरी को कठिन बना दिया है और व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाई है। बेनामी संपत्ति अधिनियम और भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून जैसे कदमों ने भ्रष्टाचारियों के मन में कानून का भय पैदा किया है।भ्रष्टाचार केवल फाइलों या दफ्तरों तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक प्रवृत्ति भी है। अक्सर हम तंत्र को दोष देते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए शॉर्टकट खोजने से नहीं चूकते। यहाँ यह नारा अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है—सुधार की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। यदि समाज भ्रष्टाचार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना शुरू कर दे और नागरिक लेने और देने दोनों से इनकार कर दें, तो कोई भी भ्रष्ट तंत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा का मंत्र हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी एक व्यक्तिगत विकल्प है जो आगे चलकर एक सामाजिक क्रांति का रूप ले लेती है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में सत्यनिष्ठा अपनाता है, तो भ्रष्टाचार की जड़ें अपने आप कमजोर होने लगती हैं। कानून और तकनीक भ्रष्टाचार को कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसे जड़ से मिटाने के लिए सामाजिक चेतना और जागरूकता अनिवार्य है। जब तक समाज में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस (शून्य सहनशीलता) का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक इस बुराई का पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं है। आगामी समय में हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

नैतिक शिक्षा- स्कूलों और परिवारों में ईमानदारी को सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्थापित करना।

व्हिसलब्लोअर का संरक्षण- उन साहसी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं।

प्रशासनिक जवाबदेही- लोक सेवकों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना ताकि वे स्वयं को स्वामी नहीं बल्कि सेवक समझें।

निष्कर्ष यह कि 9 दिसंबर का यह दिन केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा का दिन है। भारत आज विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इस गौरवशाली यात्रा में भ्रष्टाचार की बेड़ियाँ हमारे पैरों में नहीं पड़नी चाहिए। सरकार ने नीतिगत स्तर पर पारदर्शिता का जो ढांचा तैयार किया है, उसे सशक्त बनाने की जिम्मेदारी अब समाज की है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब 140 करोड़ भारतीय यह ठान लेंगे कि वे न तो भ्रष्टाचार का हिस्सा बनेंगे और न ही इसे मूकदर्शक बनकर सहेंगे। आइए, इस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर हम स्वयं से सुधार का संकल्प लें, क्योंकि पारदर्शी भारत ही समृद्ध भारत की नींव है।

(लेखक- मध्यप्रदेश के अधिमान्य पत्रकार हैं।)

(यह लेखक के व्यक्तिगतविचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

ज्ञान के रास्ते पर

गौतम बुद्ध के प्रवचन में एक व्यक्ति रोज आता था और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचन में लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार छोड़ने की बात करते थे। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर बोला- मैं लगभग एक महीने से आपके प्रवचन सुन रहा हूं। पर क्षमा करें, मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्या मुझमें कोई कमी है?

बुद्ध ने मुस्कराकर पूछा- यह बताओ, तुम कहां के रहने वाले हो?

उस व्यक्ति ने कहा- श्रावस्ती।

बुद्ध ने पूछा- श्रावस्ती यहां से कितनी दूर है?, उसने दूरी बताई।

बुद्ध ने पूछा- तुम वहां कैसे जाते हो?

व्यक्ति ने कहा- कभी घोड़े पर तो कभी बैलगाड़ी में बैठकर जाता हूं।

बुद्ध ने फिर प्रश्न किया- कितना समय लगता है?, उसने हिसाब लगाकर समय बताया।

बुद्ध ने कहा- यह बताओ क्या तुम यहां बैठे-बैठे श्रावस्ती पहुंच सकते हो

व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा- यहां बैठे-बैठे भला वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। इसके लिए चलना तो पड़ेगा या किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा।

बुद्ध मुस्कराकर बोले- तुमने बिल्कुल सही कहा। चलकर ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का प्रभाव भी तभी पड़ता है जब उन्हें जीवन में उतारा जाए। उसके अनुसार आचरण किया जाए। कोई भी ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे व्यावहारिक जीवन में उतारा जाए। मात्र प्रवचन सुनने या अध्ययन करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता।

उस व्यक्ति ने कहा- अब मुझे अपनी भूल समझ में आ रही है। मैं आपके बताए मार्ग पर आज से ही चलूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया।

विचार मंथन

सुप्रीम कोर्ट का त्वरित सुनवाई से इनकार

(लेखक- सनत जैन)

भारत में इंडिगो द्वारा पिछले एक सप्ताह में हजारों फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद सहित अन्य एयरपोर्ट में अभी तक हजारों फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले ही इंडगो एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ाने रद्द कर दी थीं। देश के सभी एयरपोर्ट में मारामारी मची हुई है। देसी और विदेशी यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं। उनका सामान उन्हें वापस नहीं मिल रहा है। फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना उन्हें समय पर नहीं दी गई। जो यात्री विमानतल के अंदर थे, उनकी सुख-सुविधा का ध्यान भी नियमानुसार इंडिगो ने नहीं रखा। यात्रियों में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह से परेशान होते रहे। बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिला। महिलाओं को सैनिटरी पेड नहीं मिले। 24 घंटे से ज्यादा हवाई यात्री विमानतलों पर कैद रहे। उनको सुनने वाला कोई नहीं था। उन्हें विमानतल पर खाना नहीं मिला। इससे बड़ी अव्यवस्था क्या हो सकती थी। इंडिगो एयरलाइंस अपनी जिम्मेदारी से लगातार भागती रही। अन्य एयरलाइन कंपनियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। 40,000 से लेकर 100000 रूपये तक में टिकट बेची गई। सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। यात्री परेशान होते रहे। पिछले एक सप्ताह से भारत के विमानतलों पर जिस तरह से यात्री परेशान हो रहे हैं, उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। इसके बाद भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से विमानन कंपनी इंडिगो के सामने आत्मसमर्पण करते हुए दिख रहे हैं, उसको लेकर यात्रियों में भारी गुस्सा है। हर कोई अपनी जवाबदारी से बच रहा है। हवाई जहाज के यात्रियों को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है। सरकार ने चार दिन बाद इंडगो एयरलाइन कंपनी से कहा, वह यात्रियों के टिकट के पैसे रविवार की शाम तक वापस कर दे। सरकार ने कारण बताओ नोटिस देकर इति श्री कर ली। हजारों की संख्या में यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई थी। कई को विदेश जाने की फ्लाइट नहीं मिली। हवाई यात्रियों को तरह-तरह की परेशानियां अभी भी हो रही हैं। देसी और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। डीजीसीए के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। उड्डयन मंत्रालय भी इंडिगो एयरलाइंस के सामने बेबस नजर आ रहा है। जिस तरह की स्थिति भारत में बनी है, उसको लेकर सारी दुनिया के देशों में भारत ओर एयरलाइन कंपनियों की सेवाओं को लेकर तरह-तरह की चर्चा होने लगी है। सारे विश्व में भारत की छवि धूमिल हो गई है। भारत में नियम-कानून और कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह की स्थिति है इसे सारी दुनिया के देशों ने जान लिया है। 50000 से ज्यादा देसी और विदेशी यात्री पिछले एक सप्ताह से परेशान होकर यहां से वहां भटक रहे हैं। इतने गंभीर मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस मामले को यह कहते हुए सुनने से मना कर दिया है, भारत सरकार पहले ही एक्शन ले चुकी है। इस मामले की सुनवाई वह 10 दिसंबर को करेंगे। सरकार ने क्या एक्शन लिया है यह भी सुप्रीम कोर्ट ने जानने की जहमत नहीं उठाई। मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी, वह एयरलाइन नहीं चला सकते हैं। इससे भारत के लोगों को बड़ी निराशा हुई है। नागरिकों का मानना था, कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई करता। यात्रियों को फौरी तौर पर राहत देने के लिए कोई आदेश करता। वह तो सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं। जब यात्रियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई गई। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण जिन यात्रियों को परेशानी हो रही है। उन्हें तत्काल राहत देने के निर्देश केंद्र सरकार और विमानन कंपनी को दिए जाएं। नियमों का पालन एयरलाइन कंपनी से कराया जाए। यात्रियों से जिस तरह का मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिका की तत्काल प्रारंभिक सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। इस कारण यात्रियों को कहीं से भी कोई राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। यात्रियों को तत्काल राहत की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और कंपनियों के भरोसे हजारों यात्रियों को उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया, जो उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से यात्री परेशान हैं। उनके साथ छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी हैं। जो बुरी तरह से परेशान हैं। सरकार और विमानन कंपनियां गंभीरता के साथ यात्रियों की परेशानी का निराकरण कर रही होती। यात्रियों को राहत पहुंचाने का कोई प्रयास कर रही होती। तो यात्रियों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में याचिका लगाने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से न्यायपालिका ने मामले को सुनने से इनकार किया है। इसके बाद यह धारणा बनने लगी है। न्यायपालिका

इंडिगो के शेयर में भारी गिरावट, एक दिन में 13,774 करोड़ का नुकसान

- कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,93,875.18 करोड़ हुआ

नई दिल्ली । इंडिगो एयरलाइंस की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के निवेशकों के लिए सोमवार, 8 दिसंबर का दिन मुश्किल भरा रहा। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयरों में तेज दबाव आया और बीएसई पर स्टॉक लगभग 7 फीसदी गिरकर 5,015 के इंट्राडे लो पर पहुंच गया। शुक्रवार तक कंपनी का मार्केट कैप 2,07,649.40 करोड़ था, जो सोमवार को घटकर 1,93,875.18 करोड़ रुपए रह गया। निवेशकों को एक दिन में 13,774.22 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। शेयरों में गिरावट उस समय आई जब डीजीसीए के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस के जवाब की समयसीमा एक दिन बढ़ाई। एयरलाइन से पूछा गया कि हजारों यात्रियों को प्रभावित करने वाली उड़ानों में देरी और रद्दीकरण क्यों हुआ। डीजीसीए ने बताया कि यह संकट नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को लागू करने में इंडिगो की कमजोर तैयारी के कारण उत्पन्न हुआ। एक ही दिन में 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जो भारतीय एविएशन इतिहास में किसी भी एयरलाइन द्वारा एक दिन में सबसे ज्यादा कैंसिलेशन है।

अदाणी ग्रीन ने टीएनएफडी ढांचे को अपनाया

नई दिल्ली । अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीएल) ने प्रकृति-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (टीएनएफडी) ढांचे को अपनी मुख्य स्थिरता रणनीति में शामिल किया है। यह वैश्विक, विज्ञान-आधारित ढांचा कंपनियों को प्रकृति-संबंधी जोखिम और अवसरों की पहचान, प्रबंधन और प्रकटीकरण में मदद करता है। कंपनी ने इंडिया बिजनेस बायोडायवर्सिटी इनीशिएटिव (आईबीबीआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। एजीएल ने 2030 तक जैव विविधता में 'नो नेट लॉस' सुनिश्चित करने और परियोजना स्थलों पर 2.786 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई है। एजीएल के पास वर्तमान में 16.5 गीगावाट से अधिक की क्षमता है, जो भारत में सबसे बड़ी है और 12 राज्यों में फैली है। कंपनी का लक्ष्य है 2030 तक 50 गीगावाट क्षमता हासिल करना। एजीएल के सीईओ आशीष खन्ना ने कहा कि प्रकृति कंपनी की वृद्धि का केंद्र है और टीएनएफडी अपनाकर नवीकरणीय ऊर्जा और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के अवसरों की पहचान हो रही है।

स्वास्थ्य उद्योग ने पान मसाला उत्पादन पर उपकर का किया स्वागत

विधेयक का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना

नई दिल्ली । नई संसद में पारित स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। इस विधेयक के तहत विशेष रूप से पान मसाला जैसे अस्वास्थ्यकर उत्पादों के विनिर्माण या उत्पादन पर उपकर लगाया जाएगा। उद्योग विशेषज्ञों ने इसे प्रगतिशील कदम करार दिया है, क्योंकि इससे अस्वास्थ्यकर उत्पादों से होने वाले लाभ को सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। विशेष बात यह है कि यह उपकर उत्पाद की वास्तविक मात्रा पर नहीं, बल्कि उत्पादन क्षमता पर आधारित होगा। इसमें मशीनों की प्रकार, गति, भार उठाने की क्षमता और मैनुअल प्रक्रियाओं की प्रकृति शामिल होगी। इसका मतलब यह है कि चाहे उत्पादन मशीनों या हाथों से हो, दोनों पर उपकर लागू होगा। विनिर्माताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा और हर महीने की 7 तारीख तक उपकर का भुगतान करना अनिवार्य होगा। उद्योग को अपनी मशीनरी और मैनुअल प्रक्रियाओं की पूरी घोषणा करनी होगी। उद्योग और विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम अस्वस्थ उत्पादों से होने वाले लाभ को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश करने की दिशा में समय की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीतिगत बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा के बराबर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकेत देता है। इस विधेयक से भारत को गैर-संचारी रोगों, संक्रामक रोगों और मातृ-शिशु स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन सुनिश्चित होंगे। विशेषज्ञ इसे स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोड़ने वाले क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं।

वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाया में छूट और पुनर्गणना का प्रस्ताव दिया

कंपनी अपने वित्त से ब्याज का भुगतान करने में सक्षम होगी

नई दिल्ली ।

पिछले कई वर्षों से वित्तीय संकट झेल रही निजी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआई) ने दूरसंचार विभाग को प्रस्ताव सौंपा है। कंपनी ने एजीआर (एडजस्टड ग्रास रेवेन्यू) बकाया की पुनर्गणना करने और जुर्माने तथा ब्याज पर एकमुश्त छूट देने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव में बकाया राशि की गणना में मौजूद अंकगणितीय त्रुटियों और दोहराव को हटाकर इसे समायोजित करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार इससे बकाया राशि करीब आधी हो सकती है, जिससे कंपनी अपने वित्त से ब्याज का भुगतान करने में सक्षम होगी।

वित्त वर्ष 2017 तक वीआई की एजीआर देनदारी 58,254 करोड़ रुपये थी। इसमें मूल राशि 12,797 करोड़, ब्याज 28,294 करोड़, जुर्माना 6,012 करोड़ और जुर्माने पर ब्याज 11,151 करोड़ शामिल थे। मार्च 2025 तक कुल देनदारी बढ़कर 83,400 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें वित्त वर्ष 2019 तक के लाइसेंस शुल्क के 9,450 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। कंपनी की 25,000 करोड़ रुपये की फंडिंग प्रक्रिया, 50,000-55,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय योजना का हिस्सा है। यह निवेश वीआई को 5जी सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करेगा। सूत्रों ने बताया कि सर्कल स्तर पर एजीआर की पुनर्गणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

यह प्रस्ताव सितंबर में सर्वोच्च न्यायालय में पेश संशोधित याचिका के अनुरूप है, जिसमें वीआई ने कहा था कि बकाया राशि के कई घटक अंतिम रूप नहीं दिए गए थे।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2017 तक अपने एजीआर बकाया की व्यापक पुनर्गणना और देनदारियों की पुनर्मूल्यांकन की मांग की है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ 12 को खुलेगा

नई दिल्ली । आईसीआईसीआई बैंक की अनुषंगी कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (ने अपने आगामी आईपीओ के लिए 2,061 से 2,165 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। इससे कंपनी का अनुमानित मूल्यांकन 1.07 लाख करोड़ रुपए (लगभग 11.86 अरब डॉलर) हो गया है। कंपनी का आईपीओ 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक खुलेगा। बड़े (एंकर) निवेशक 11 दिसंबर से बोली लगा सकते हैं। यह आईपीओ पूरी तरह प्रवर्तक द्वारा 4.89 करोड़ से अधिक शेयरों की ऑफर फॉर सेल पर आधारित है। निवेशक इस अवसर के माध्यम से सीधे प्रवर्तक से शेयर खरीद सकेंगे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर को स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हो सकते हैं।

एचडी ह्युंडै तूतीकोरिन में 2 अरब डॉलर के निवेश से शिपयार्ड स्थापित करेगी

परियोजना से अनुमानित 55,000 रोजगार के मिलेंगे अवसर

नई दिल्ली ।

दक्षिण कोरियाई जहाज निर्माण कंपनी एचडी ह्युंडै की प्रमुख इकाई एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (एचडी केएसओई) तमिलनाडु के तूतीकोरिन में नया शिपयार्ड स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना में करीब 2 अरब डॉलर का निवेश होने का अनुमान है। प्रारंभ में इसे शिपबिल्डिंग मेक इन इंडिया टुगेदर विद ह्युंडै के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब इसे शिपबिल्डिंग मेक इन तमिलनाडु विद ह्युंडै कहा जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उद्योग मंत्री टीआरबी राजा के अनुसार तूतीकोरिन में शिपयार्ड के लिए विश्वस्तरीय जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। राज्य ने स्पष्ट नीतिगत ढांचा, तेज समन्वय, और मजबूत तटीय वातावरण होने के कारण एचडी हुंडै का भरोसा जीत लिया। परियोजना के लिए व्यवहार्य स्थलों की पहचान और उन्हें प्रतिभा, बुनियादी ढांचा और प्रोत्साहन के साथ समर्थन भी प्रदान किया गया है। जहाज निर्माण श्रम-सघन उद्योग है और इससे कई सहायक क्षेत्रों को लाभ होता है। एक प्रत्यक्ष नौकरी से लगभग छह अप्रत्यक्ष नौकरियां बनती हैं। इस परियोजना से अनुमानित 55,000 रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा, कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक भी तूतीकोरिन में अलग-अलग परियोजनाओं के तहत निवेश कर रहे हैं, जिनका कुल मूल्य 30,000 करोड़ रुपये है। राज्य शिपयार्ड विकास को प्राथमिकता दे रहा है ताकि तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, निवेश आकर्षित और प्रतिभा तैयार की जा सके। पिछले चार वर्षों में राज्य में लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 10 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं।

शेयर बाजार गिराट के साथ बंद

सेंसेक्स 609 अंक , निफ्टी 225 अंक फिसला

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच ही बिकवाली हावी होने से बाजार नीचे आया है। दिन भर के के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स अंत में 609.68 अंक टूटकर 85,102.69 पर वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 225.90 अंक फिसलकर 25,960.55 पर बंद हुआ। सभी सूचकांक आज नुकसान के साथ ही लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी इंडिया डिफेंस , निफ्टी रियल्टी , निफ्टी पीएसयू बैंक , निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसई और निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा गिरे। वहीं सेंसेक्स पैक में बीईएल, , ट्रेंट, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, एसबीआई, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा के शेयर गिरे। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों को लाभ हुआ है। लार्जकैप की जगह पर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अधिक बिकवाली रही। निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक 1,106.50 अंक बढ़कर 59,488.10 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक 456.10 अंक टूटकर 17,051.65 पर था।

शेयर बाजार में गिरावट का कारण दुनिया भर से मिले कमजोंर संकेत बताय गये हैं । वहीं आने वाले समय में निवेशकों की निगाहें अमेरिकी फेड के परिणामों पर रहेंगी।

इससे पहले आज सुबह घरेलू बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स पिछले सत्र की तुलना में 109 अंक नीचे खेला। वहीं निफ्टी भी 26,153 के स्तर पर मामूली कमजोरी के साथ खुला। हालांकि शुरुआती घंटे में बाजार में कुछ स्थिरता दिखी, लेकिन इसके बाद करीब बिकवाली तेज हो गई, जिससे प्रमुख सूचकांकों पर दबाव बढ़ा।

एशियाई बाजार में आज मिले-जुले रुझान दिखे। चीन का सीएसई 300 0.48 फीसदी बढ़ा जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.07 फीसदी गिरा। निवेशक चीन के नवंबर के व्यापार आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। जापान का निक्केई 0.32 फीसदी नीचे गया क्योंकि तीसरी तिमाही में जीडीपी में गिरावट शुरुआती अनुमान से ज्यादा रही। अमेरिकी बाजार अमेरिकी शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी रही। डाउ जोंस 0.22 फीसदी, एसएंडपी 500 0.19 फीसदी और नैस्डैक 0.31 फीसदी ऊपर बंद हुआ।

रुपये में जारी गिरावट को रोकने ....आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो रुपये में गिरावट को कम कर सकता है और फिर को फिर ऊपर ला सकता है। यह फैसला तब लिया गया है, जब रुपया 90 के ऊपर चला गया था। हालांकि अभी इसमें कुछ तेजी आई है।

दरअसल, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताया। इसमें 25 आधार अंकों की ब्याज दर में कटौती करने का भी ऐलान किया, लेकिन इसके साथ ही लिक्वि डिटी बढ़ाने पर भी फैसला लिया। आरबीआई ने दिसंबर में 1 लाख करोड़ रुपये की ओपेन मार्केट में खरीदारी, और 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अदला-बदली का ऐलान किया।

ओपेन मार्केट से की जाने वाली इन दो बड़ी खरीदों का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में कैश की मात्रा को बढ़ाना है। जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है, तब वह बैंकों को एडवांस पेमेंट करता है और सीधे सिस्टम में पैसा आता है। इससे करेंसी मार्केट में दरें आसान होती है और किसी भी तरह की लिक्विडिटी संकट कम आती है। लिक्विडिटी की कमी अक्सर रुपये पर दबाव बढ़ा देती है, क्योंकि विदेशी निवेशक शॉर्ट टर्म फंडिंग की स्थिति में सतर्क हो जाते है। 1 लाख करोड़ रुपये का ओएमओ आरबीआई का यह संकेत देने का तरीका है कि फंडिंग का मार्केट सही तरह से चलता रहे।

रिपोर्ट के मुताबिक जानकार ने कहा कि ओएमओ और स्वैप मिलकर जीडीपी वृद्धि के संशोधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तरलता प्रदान करेंगे और महंगाई या करेंसी की चाल पर चिंता के बजाय पॉजिटिव और आशा से प्रेरित नजरिए को उभारने वाले है। 5 अरब अमेरिकी डॉलर का स्वैप करेंसी के ज्यादा करीब काम करता है। अभी डॉलर खरीदकर और बाद में उन्हें वापस बेचने का वादा करके, आरबीआई अपने भंडार को स्थायी रूप से कम किए बिना, सिस्टम में रुपया जारी करता है। यह स्वैप तत्काल लिक्विडिटी पेश करता है और मार्केट को यह विश्वास दिलाता है कि आरबीआई तेज उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए तैयार है।

रुपये के नए निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की इच्छा ने कुछ जानकारों को चौंका दिया है, लेकिन कुछ जानकार एक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। आरबीआई के इस रुख से पता चलता है कि रुपये में हालिया गिरावट ज्यादा बढ़ गई है और करेंसी में मौजूदा स्तरों पर कमतर आंकी गई है। उनका कहना है कि आरबीआई की भाष से यह विश्वास झलकता है कि महंगाई अनुकूल रहने पर रुपया स्थिर हो सकता है। एक्सपर्ट ने कहा कि लिक्विडिटी का सपोर्ट रुपये को सीधे तौर पर ऊपर नहीं उठाता, यह केवल एक अनियंत्रित गिरावट को रोक सकता है। जब फंडिंग की स्थिति सही होगी और ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा हो, तब विदेशी निवेशकों के अचान बाह निकलने की संभावना कम होती है। इससे अस्थिरता कम होती है और उम्मीदें स्थिर रहती हैं।

पुराने नामों से नई पहचान : ऑटो कंपनियों की रणनीति रंग ला रही

नई दिल्ली ।

भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां पुराने और प्रसिद्ध ब्रांड नामों का इस्तेमाल करके ग्राहकों का ध्यान खींच रही हैं। नए मॉडल्स की भीड़ में यह रणनीति कंपनियों को अलग पहचान बनाने और पुराने ग्राहकों की भावनाओं से जुड़ने में मदद करती है। आईसीआरए के एक व रिष्ठ अ धिकारी के अनुसार, पुराने ब्रांड्स में पहले से भरोसा और पहचान मौजूद होती है, इसलिए नए मॉडल जल्दी अपनाए जाते हैं और मार्केटिंग खर्च भी कम होता है। टाटा मोटर्स ने लगभग तीन दशक बाद सिएरा को वापस लाया और 2021 में सफारी को रिवाइवल किया। मारुति सुजुकी ने 2015 में बालेनो को प्रीमियम हैचबैक के रूप में लॉन्च किया। हुंडै ने 2018 में सेंट्रो को पुन: पेश किया, जबकि महिंद्रा ने 2022 में स्कॉर्पियो-एन और स्कॉर्पियो क्लासिक लॉन्च किया। अन्य उदाहरणों में मारुति ग्रैंड विटारा और महिंद्रा बोलेरो नियो शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पुराने नाम में भरोसा और पहचान होती है, लेकिन डिज़ाइन और फीचर्स सही न हों तो सफलता नहीं मिलती। पुराने नाम के साथ आधुनिक इंजीनियरिंग जोड़कर कंपनियां पुराने और नए दोनों ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।

नवंबर में मोटर वाहन बिक्री बढ़ी, यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की मांग मजबूत

- नवंबर में कुल बिक्री 33,00,832 इकाइयां, पिछले वर्ष की 32,31,526 इकाइयों की तुलना में 2 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली ।

त्योहारों के बाद भी मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री में तेजी बनी रही। एक ऑटोमोबाइल डीलर्स एसो सिएशन के अनुसार नवंबर 2025 में कुल बिक्री 33,00,832 इकाइयां, पिछले वर्ष की 32,31,526 इकाइयों की तुलना में 2 फीसदी बढ़ी। इस वृद्धि का मुख्य कारण यात्री वाहन, तिपहिया वाहन, वाणिज्यिक वाहन और ट्रैक्टर की मजबूत मांग रही। नवंबर में यात्री वाहनों का पंजीकरण 3,94,152 इकाई रहा, जो सालाना आधार पर 20 फीसदी अधिक है। जीएसटी में कटौती, विवाह सीजन की मांग, लोकप्रिय मॉडलों की बेहतर उपलब्धता और कॉम्पैक्ट एसयूवी की निरंतर मांग ने इस वृद्धि को बल दिया। दोपहिया वाहनों की बिक्री 25,46,184 इकाई रही, जो पिछले साल की तुलना में 3 फीसदी कम है। वाहन स्टॉक का समय घटकर 44-46 दिन रह गया, जो बेहतर मांग-आपूर्ति संतुलन को दर्शाता है। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 94,935 इकाई रही, सालाना आधार पर 20 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, माल ढुलाई, सरकारी निविदाओं और जीएसटी सुधारों ने इस वृद्धि में योगदान दिया। तिपहिया वाहनों की बिक्री 1,33,951 इकाई रही, जिसमें 24 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। ट्रैक्टर पंजीकरण 1,26,033 इकाई पर पहुंचा, जो पिछले साल की तुलना में 57 फीसदी अधिक है। मजबूत ग्रामीण आय और फसल से जुड़ी मांग ने इसे बढ़ावा दिया। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसो सिएशन के अनुसार के अनुसार अगले तीन महीनों के लिए बिक्री परिदृश्य सकारात्मक है। जनवरी में मूल्य वृद्धि, नए मॉडलों की पेशकश और ग्रामीण मांग के कारण बिक्री में और बढ़ोतरी की संभावना है। 74 फीसदी डीलरों को सभी क्षेत्रों में वृद्धि की उम्मीद है।

कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट नीतिगत दर में कटौती से उत्साहित

- पीएफसी-सिडबी बॉन्ड मार्केट में उतारेंगे 11,500 करोड़ के इश्यू

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती की है। इससे बैंकों के लिए उधार सस्ता हुआ और बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को मजबूती देने के लिए सकारात्मक संकेत है। सरकारी वित्तीय संस्थाएं, पीएफसी और` सिडबी मंगलवार को बॉन्ड मार्केट से कुल 11,500 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही हैं। इससे निवेशकों के बीच दीर्घकालिक बॉन्ड में रुचि बढ़ने की संभावना है। हालांकि, पहले उच्च यील्ड के कारण पीएफसी ने 25 नवंबर को 3 वर्षीय बॉन्ड जारी करने का निर्णय वापस ले लिया था। नीतिगत घोषणाओं के बाद बाजार की धारणा में सुधार आया है। आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) और रुपये-अमेरिकी डॉलर स्वैप से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है कि नकदी की स्थिति अनुकूल रहेगी। कई फंड और संस्थाएं तत्काल निवेश नहीं कर रही हैं। उनका ध्यान

लंबी अवधि के निर्गमों पर है, ताकि भविष्य निधि और पेंशन फंड से राशि आकर्षित की जा सके। बड़े फंड पहले से पूंजी लगाने को प्राथमिकता देते हैं ताकि नियामक और परिसंपत्ति आवंटन आवश्यकताएं पूरी हों। अक्टूबर में कंपनियों ने कॉरपोरेट बॉन्ड के जरिए 17,500 करोड़ रुपये जुटाए थे। भारती टेलीकॉम ने दो खंडों में 10,500 करोड़ रुपये जुटाए। यह दिखाता है कि बॉन्ड बाजार में निवेशकों की रुचि लगातार बनी हुई है।

चीन का निर्यात नवंबर में 5.9 प्रतिशत बढ़ा

- अमेरिका के निर्यात में 29 प्रतिशत की गिरावट

हांगकांग ।

चीन के निर्यात ने नवंबर 2025 में 5.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की और कुल 330.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह अक्टूबर में 1.1 फीसदी गिरावट के बाद सुधार को दर्शाता है और अर्थशास्त्रियों के अनुमानों से बेहतर रहा। चीन के अन्य प्रमुख बाजार जैसे दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में निर्यात में बढ़ोतरी हुई, जबकि अमेरिका की ओर निर्यात में लगातार आठवें महीने दोहरे अंकों की गिरावट के साथ लगभग 29 फीसदी की कमी देखी गई। नवंबर में आयात में 1.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो अक्टूबर की एक फीसदी वृद्धि से बेहतर रही। हालांकि संपत्ति क्षेत्र की मंदी अब भी उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश पर दबाव डाल रही है। फैक्ट्री गतिविधियां लगातार आठवें महीने घट रही हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उद्योग क्षेत्र में कमजोरी बनी हुई है। अक्टूबर के अंत में हुई बैठक में अमेरिका और चीन ने एक साल के लिए व्यापार युद्ध विराम पर सहमति बनाई। अमेरिका ने शुल्क कम किए और चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात नियंत्रण समाप्त करने का वादा किया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्यात के लिए अस्थायी सकारात्मक संकेत है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है। चीन के निर्यात की मजबूती से अर्थशास्त्री मानते हैं कि देश इस वर्ष लगभग 5 फीसदी आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य पूरा कर लेगा। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि 2030 तक चीन की वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी 16.5 फीसदी तक पहुंच जाएगी। यह वृद्धि मुख्य रूप से उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स और बैटरी जैसे उच्च-विकासशील क्षेत्रों में होगी।

एनएसई ने एफएंडओ मार्केट में पहली बार प्री-ओपन सेशन शुरू किया

8 दिसंबर 2025 से लागू नई व्यवस्था में 15 मिनट का प्री-ओपन

नई दिल्ली ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने सोमवार 8 दिसंबर से फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफएंडओ) मार्केट में पहली बार प्री-ओपन सेशन शुरू कर दिया है। यह कदम भारतीय डेरिवेटिव मार्केट की संरचना में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। एक्सचेंज का मानना है कि इससे कीमत तय करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी और मार्केट ओपन होते ही आने वाले तेज उतार-चढ़ाव में कमी आएगी। यह प्रणाली कैश मार्केट में चल रहे प्री-ओपन सेशन की तर्ज पर बनाई गई है। नया प्री-ओपन सेशन सुबह 9:00 बजे से 9:07/9:08 बजे तक चलेगा। इस दौरान निवेशक अपने ऑर्डर डाल सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं या आवश्यकता होने पर रद्द भी कर सकते हैं। यह सेशन 9:07 से 9:08 के बीच किसी भी समय समाप्त हो सकता है। विशेष रूप से निवेशक मार्केट और लिमिट दोनों तरह के ऑर्डर दे सकेंगे, लेकिन **स्टॉप लॉस और आईओसी ऑर्डर को अनुमति नहीं होगी। शुरुआत में यह प्रणाली केवल करेंट-मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स* पर लागू होगी, जबकि महीने के अंतिम पांच दिनों में नेक्स्ट-मंथ कॉन्ट्रैक्ट् भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ऑर्डर एंट्री समय समाप्त होने के बाद 9:08 से 9:12 बजे तक एनएसई ऑर्डर मैचिंग प्रक्रिया चलाएगा। पहले लिमिट ऑर्डर आपस में मिलाए जाएंगे, उसके बाद बची हुई लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर से मैच होंगी। अंत में मार्केट ऑर्डर एक-दूसरे से मिलाए जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद जो कीमत निकलती है और जिस स्तर पर सर्वाधिक खरीद-बिक्री संभव होती है, उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। यही बाजार की ओपनिंग प्राइस बनेगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने उतरेगी भारतीय टीम

कटक (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम यहां मंगलवार को पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करने के इरादे से उतरेगी । इससे पहले हुई एकदिवसीय सीरीज में जीत से भारतीय टीम के हौंसले बुलंद हैं। इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव, वहीं दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी एडन मार्कराम के पास रहेगी। इसी मैच को जीतकर सीरीज में दोनो ही टीम बढ़त लेने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय टीम के लिए राहत की बात ये है कि शुभमन गिल फिट हो गये हैं और वह इस मैच में खेलेंगे। उनके अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी इस सीरीज से वापसी करेंगे।

ये सीरीज अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। इससे दोनों टीमें अपनी अपनी तैयारियों का आंकलन करेंगी। भारतीय टीम की बल्लेबाजी आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के अलावा , तिलक वर्मा, कप्तान सूर्यकुमार व शुभमन गिल पर अधारित रहेगी। वहीं गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे। स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव रहेंगे। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी मार्कराम के अलावा डेविड मिलर, क्विंटन डी कॉक पर आधारित रहेगी। गेंदबाजी की कमान केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी व, एनरिक नोर्खिया संभालेंगे।

टीमें इस प्रकार हैं

भारतीय टीम : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर।

दक्षिण अफ्रीका : एडन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जेनसन, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फरेरा, ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्खिया।

अभिषेक एक साल में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक अहम रिकार्ड बनाया है जिससे अंदाजा होता है कि वह कितने अच्छे फार्म में हैं। अभिषेक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही पंजाब की कप्तानी करते हुए 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये हैं। इस बल्लेबाज ने 6 मुकाबलों में 300 से अधिक रन बनाये हैं। सर्विसेज के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने तीन छक्के लगाकर अर्धशतक बनाया था।

अभिषेक इसी के साथ ही एक एक कैलेंडर ईयर में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बने हैं। अभिषेक ने सर्विसेज के खिलाफ एलीट ग्रुप सी मैच में 34 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की सहायता से 62 रन की आक्रामक खेली। इस मैच में दूसरा छक्का लगाते ही अभिषेक एक साल में 100 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं।

अभिषेक ने इस साल भारतीय टीम की ओर से 17 टी20आई मैचों में 47 छक्के लगाए हैं। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 14 मैचों में 28 छक्के लगाये हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 2025 सत्र में अभिषेक ने अब तक 6 मैचों में 26 छक्के लगाए हैं। कुल मिलाकर इस साल अब तक खेले गए 37 टी20 मैचों में उनके नाम 101 छक्के हैं। अभिषेक ने पिछले साल भी 39 मैच में सबसे अधिक 39 87 छक्के लगाए थे। वहीं साल 2022 में सूर्यकुमार यादव ने 41 टी20 मैचों में 85 छक्के लगाए थे।टी20 में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान निकोलस पूरन के नाम है। साल 2024 में पूरन ने 76 मैच में 170 छक्के लगाए थे। इस साल उन्होंने डरबन सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, एमआई अमीरात, एमआई न्यूयॉर्क, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स (पुरुष), रंगपुर राइडर्स, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और वेस्टइंडीज की ओर से खेला था। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल विश्व के पहले खिलाड़ी थे, जिन्होंने टी20 में एक कैलेंडर ईयर में 100 छक्के लगाए थे।

जसप्रीत बुमराह के पास तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका

नई दिल्ली । भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कुछ ऐतिहासिक माइलस्टोन्स बनाने की कगार पर हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार से कटक में टी20आई सीरीज शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार के बाद वनडे में वापसी करते हुए भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की लीडरशिप में टीम इंडिया टी20 में अभी तक कोई सीरीज नहीं हारी है और प्रोटियाज के खिलाफ बड़ी सीरीज़ जीतकर घरेलू टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को तेज करने का लक्ष्य रखेगी, यह टीम अनुभव और युवाओं के जोश से बराबर भरी हुई है।

बुमराह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बाद भारत के लिए टी20आई विकेटों का शतक लगाने वाले दूसरे बॉलर बनने की लाइन में हैं। इसके लिए बुमराह को सिर्फ एक विकेट की जरूरत है। उन्होंने 80 टी20आई में 18.11 के औसत से 99 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट फिगर 3/7 रहा है। टॉप पर अर्शदीप (68 मैचों में 105) हैं। इसके साथ बुमराह खेल के सभी फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर बन जाएंगे। बुमराह साथ ही सभी फॉर्मेट में 500 विकेट लेने वाले आठवें भारतीय बॉलर बनने से 18 विकेट दूर हैं। 221 मैचों में बुमराह ने 20.60 के औसत से 482 विकेट लिए हैं जिसमें उनके नाम 6/19, 13 चार विकेट हॉल और 18 बार 5 विकेट हॉल का बेस्ट रिकॉर्ड है।

जोफ्रा आर्चर पर भड़के रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ के साथ तीखी बहस के लिए साधा निशाना

ब्रिस्बेन (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने गाबा में खेले गए दूसरे एशेज टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के अचानक सामने आए जोश पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच आठ विकेट से जीता, लेकिन अंतिम चरण में आर्चर की तेज़ गेंदबाज़ी और स्टीव स्मिथ से हुई बहस सोशल मीडिया पर छा गई। पोंटिंग के अनुसार, आर्चर पूरे मैच में अपनी धार नहीं दिखा पाए और जब मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था, तब उनका गुस्सा उभरकर सामने आया। इस देर से दिखे आक्रामक रवैये पर पोंटिंग ने खुलकर सवाल उठाए।

पोंटिंग की कड़ी आलोचना: 'बहुत कम, बहुत देर से'

रिकी पोंटिंग ने कमेंट्री के दौरान कहा कि आर्चर की अचानक तेज़ी मैच की वास्तविक परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत थी। चौथे दिन जब इंग्लैंड 64 रन के छोटे लक्ष्य की रक्षा कर रहा था, तभी आर्चर ने 150 द्मद्वश्चद्ध के करीब रफ्तार पकड़ ली। पोंटिंग के अनुसार,

अगर यह ऊर्जा और तीखापन पहले दिखाई देता, तो इंग्लैंड मैच में बेहतर स्थिति में हो सकता था। उन्होंने स्पष्ट कहा, ÷सीरीज के छह दिन बाद आर्चर में जान आई है – वह भी तब, जब दूसरा टेस्ट लगभग खत्म हो चुका था। यह बहुत देर हो चुकी है, चैंप।÷

स्मिथ-आर्चर में गर्मागर्म बहस

ऑस्ट्रेलिया के जीत सुनिश्चित करने से कुछ मिनट पहले आर्चर और स्मिथ के बीच हुए वाक्य-विवाद ने माहौल और गर्म कर दिया। आर्चर ने स्मिथ को कई बाउंसर फेंककर उकसाया, जिस पर स्मिथ ने तीखे शब्दों में पलटवार किया। आर्चर ने कहा, 'तुम ऐसे शॉट तब ही खेलते हो जब स्कोर कम हो।' स्मिथ ने तुरंत जवाब दिया, 'तुम तेज़ बॉलिंग तभी करते हो जब कुछ नहीं बचा होता, चैंप।' यह संवाद तुरंत वायरल हो गया और मैच का सबसे चर्चित पल बन गया।

'चार दिन चूक गए इंग्लैंड': पोंटिंग का तंज

पोंटिंग ने इंग्लैंड की समग्र बॉडी लैंग्वेज और रवैये पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, इंग्लैंड चार दिन तक संघर्ष करता रहा और अचानक अंतिम घंटों में आक्रामक दिखने लगा। उन्होंने कहा, 'अब आप लड़ने निकले हो? बहुत देर हो चुकी है। चार दिन का मौका था।'

स्मिथ पर 'द वुड' होने की धारणा को पोंटिंग ने बताया गलत

2019 में लॉर्ड्स टेस्ट में लगे खतरनाक बाउंसर के बाद यह माना जाता है कि आर्चर, स्मिथ के खिलाफ मानसिक बढ़त रखते हैं। पर पोंटिंग ने इस धारणा को पूरी तरह मिथक बताया। टेस्ट क्रिकेट में आर्चर ने स्मिथ को कभी आउट नहीं किया। उन्होंने 220 गेंदों पर 130 रन दिए, जो मौजूदा सांख्यिकी के अनुसार आर्चर के प्रभुत्व वाली कहानी नहीं दिखाते।

एशेज की असली तीखी शुरुआत?

पोंटिंग ने माना कि गाबा में दिखा यह छोटा-सा भिड़ंत टेस्ट क्रिकेट की असली तीव्रता को दर्शाती है। लेकिन पहले दो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बढ़त ने इंग्लैंड के लिए चुनौती और कठिन बना दी है। उन्होंने कहा, 'अब खेल असली रूप में आ गया है। एशेज क्रिकेट इसी के लिए जाना जाता है।'

रूट के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकार्ड, ऑस्ट्रेलिया में लगातार 16 वां टेस्ट हारे

ब्रिस्बेन । इंग्लैंड की यहां एशेज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के साथ ही अनुभवी बल्लेबाज जो रूट के नाम एक ऐसा रिकार्ड दर्ज हो गया है जिसे वह भूलना चाहेंगे। अब रूट के नाम ऑस्ट्रेलिया में लगातार 16 टेस्ट में हार का

शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इससे पहले पाकिस्तान में लगातार 15 हार का रिकार्ड भारतीय टीम के महान ऑलराउंडर कपिल देव के नाम था। इनके अलावा किसी भी अन्य क्रिकेटर के नाम किसी देश में बिना किसी जीत के इतने मुकाबले हारने का रिकॉर्ड नहीं है। जिस प्राकर रूट का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड कमजोर रहा, वैसे ही कपिल देव का पाकिस्तान में व्यक्तिगत रिकॉर्ड खराब रहा है। कपिल ने पाक में 22 पारियों में 548 रन बनाए, औसत 26.10 रहा, और 44 विकेट लिए, औसत 40.02 रहा। ये उनके करियर का दूसरे सबसे खराब औसत रहा है। रूट ने हालांकि इस बार अच्छा प्रदर्शन किया था पर वह अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाये। इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाये जिससे टीम हार गयी। उसके बल्लेबाज दोनों पारियों में रन बनाने में विफल रहे। रूट ने हालांकि पहली पारी में शतक लगाया था पर उन्हें किसी से साथ नहीं मिला।

रोहित और कोहली की जगह को लेकर अब सवाल नहीं उठाने चाहिये : बांगर

विशाखापट्टनम। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बढ़ती उम्र के बाद भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में टीम में इनकी जगह को लेकर किसी भी प्रकार के सवाल नहीं उठाये जाने चाहिये। बांगर ने कहा कि पिछले कुछ समय के अंदर दोनो ने अपने प्रदर्शन से दिखा दिय है कि वे अभी भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से हैं। इसलिए इन दोनो के साथ अलग तरह से व्यवहार होना चाहिये। इसके अलावा इसकी टीम में जगह को लेकर किसी प्रकार प्रकार की आशंकाएं नहीं लगायी जानी चाहिये। इन किन ने पिछले छह एकदिवसीय मैचों में अपने को साबित किया है। ऑस्ट्रेलिय और दक्षिय अफ्रीका के खिलाफ देखा जाये तो इन दोनो ने जो खेल दिखाया वह कोई और नहीं दिखा पाया। बांगर ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि अबटीम में इनकी की जगह को लेकर सवाल उठाए जाने चाहिए। उनके इतने वर्षों में टीम को दिए गए योगदान पर ध्यान देना चाहिए।'' कोहली और रोहित अब केवल एकदिवसीय प्रारूप में ही खेलते हैं। भारतीय टीम ने पिछले कुछ समय में इस प्रारूप में बहुत कम मैच खेले हैं। बांगर का मानना है कि उन्हें लय हासिल करने में कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा, ''वे दो प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए ज़ाहिर है कि उन्हें लय हासिल करने में कुछ समय लग सकता है पर वे ऐसा कई बार कर चुके हैं। उन्हें किसी युवा खिलाड़ी जितने मैच खेलने की जरूरत नहीं है। एक बार वे जब अपनी लय हासिल कर लेते हैं तो उन्हें रन बनासे से रोकना संभव नहीं होता। ऐस में अगर आप इस तरह के खिलाड़ियों को टीम में चाहते हैं। आपको उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करना होगा और उन्हें अपना स्वाभाविक खेल खेलने की आजादी देनी होगी।''उन्होंने कहा, '''जब वे लय में होते हैं तो आपको अंतर साफ नजर आता है। उनके रहने से ही से ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल जाता है।।''

एफआईएच जूनियर विश्व कप 2025 क्वालीफाइंग मुकाबला : भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने वेल्स को 3-1 से हराया

सैंटियागो (एजेंसी)। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारतीय टीम ने एफआईएच जूनियर विश्व कप 2025 के नौ से 16वें स्थान के लिए हुए इस क्वालीफाइंग मुकाबले में वेल्स को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया। भारतीय टीम की ओर से हिना बानो ने 14वें मिनट, सुनेलिता टोप्पो ने 24वें मिनट और इशिका ने 31वें मिनट में गोल किये। वहीं वेल्स की ओर से एकमात्र गोल एलोइस मोट ने 52वें मिनट में किया।

भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत में से ही आक्रमण करने शुरु कर दिये। पहले क्वार्टर के अंत में साक्षी राणा के शानदार पास पर हिना ने गोल करा भारतीय टीम को बढ़त दिला दी। वहीं दूसरे क्वार्टर में सुनेलिता टोप्पो ने एक गोल कर भारतीय टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया।

वहीं तीसरे हाफ में इशिका से गोल से भारतीय टीम की बढ़त 3-0 की हो गयी। भारतीय टीम अपने आक्राक रुख से वेल्स पर परे समय हावी रही। वेल्स की ओर से 52वें मिनट में एलोइस मोट ने गोल कर भारतीय टीम की बढ़त को कम जरुर किया पर इसके बाद उनकी ओर से कोई खिलाड़ी गोल नहीं कर पाया।

शाकिब ने संन्यास का फैसला वापस लिया, बांग्लादेश लौटकर खेलना चाहते हैं एक घरेलू सीरीज

सेन डियागो । पिछले काफी समय से अमेरिका में रह रहे बांग्लादेश क्रिकेट टीम से पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने संन्यास से वापसी का फैसला किया है। शाकिब का कहना है कि वह एकसाथ ही तीनों प्रारुपों को अलविदा कहना चाहते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के स्पिनर मोईन अली से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने अभी तक तीनों प्रारुपों से आधिकारिक रुप से संन्यास नहीं लिया है। साथ ही कहा कि वह बांग्लादेश लौटकर एक पूरी घरेलू सीरीज खेलने के बाद ही तीनों प्रारुपों से एक साथ संन्यास लेंगे। शाकिब पिछले एक साल से ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं। उन्होंने पिछले साल ही टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया था। उन्होंने मोईन से बातचीत के दौरान कहा, मैं आधिकारिक रूप से अभी तीनों प्रारुपों से रिटायर नहीं हुआ हूं। ये पहला मौका है जब मैं इसका खुलासा कर रहा हूं। मेरी योजना है कि मैं बांग्लादेश जाकर, एक पूरी एकदिवसीय, टेस्ट और टी20 सीरीज खेलूं और फिर रिटायरमेंट लूं। शाकिब ने साथ ही कहा कि मैं तीनों प्रारुपों से एकसाथ संन्यास ले सकता हूं। मुझे बस एक पूरी सीरीज खेलनी है और फिर संन्यास लेना है। गौरतलब है कि शाकिब मई 2024 से ही बांग्लादेश वापस नहीं लौटे हैं। छात्र आंदोलन और अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटाये जाने के हटने के बाद से ही वह देश से बाहर ही हैं। शाकिब अवामी लीग से सांसद भी बने थे। उनके नाम पर कई मामले भी बांग्लादेश में दर्ज हुए थे। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान और भारत में टेस्ट मैच भी खेले। भारत के खिलाफ कानपुर में उन्होंने दूसरा टेस्ट व अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वे बांग्लादेश लौटेंगे, तो शाकिब ने कहा कि मुझे उम्मीद है। इसलिए मैं कई टी20 लीग खेल रहा हूं मुझे लगता है, ऐसा होगा। शाकिब ने ये भी कहा कि वह अपने देश में एक घरेलू सीरीज खेलकर सम्मानजनक विदाई चाहते हैं, ताकि अपने प्रशंसकों का आभार वयक्त कर सके।

भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार, अधिक बदलाव नहीं होंगे : सूर्यकुमार

कटक । भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहां होने वाले पहले टी 20 मैच में बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी टीम तैयार है। सूर्यकुमार ने बताया कि टीम का माहौल काफी अच्छा और इसमें अधिक बदलाव नहीं होंगे। सूर्या ने कहा कि मैच में ओस सहित कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। सूर्यकुमार ने कहा कि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और रात के समय ओस का गिरना स्वाभाविक है। ऐसे मुकाबलों में ओस से भी प्रभाव पड़ता है। कप्तान ने कहा कि इसमें हमारा बस नहीं है। हमें खेलना ही है, ओस अगर होगी तो उसके हिसाब से ही प्रबंधन करेंगे क्योंकि हम मैदान छोड़कर भाग तो नहीं सकते। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को एकदिवसीय सीरीज में हराया है जिससे वह इस मैच में उत्साहित होकर उतरेगी। वहीं अपने दौरे के इस अंतिम चरण में मेहमान टीम जीत हासिल करना चाहेगी।

फरवरी में नीदरलैंड के खिलाफ डेविस कप की मेजबानी करेगा भारत

मुम्बई। भारत अगले साल की शुरुआत में नीदरलैंड के खिलाफ डेविस कप मैचों की मेजबानी करेगा। ये मैच सात–आठ फरवरी को बेंगलुरु में खेले जाएंगे। डेविस कप की मेजबानी में बेंगलुरु के अलावा दिल्ली भी शामिल थी पर अंत में बेंगलुरु को मेजबानी मिली। दिल्ली लॉन टेनिस संघ (डीएलटीए) ने इस साल फरवरी में टोगो की मेजबानी की थी और उसने भी इस अहम मुकाबले को आयोजित करने में रुचि दिखाई थी। बेंगलुरु ने पिछली बार 2017 में उज्बेकिस्तान के खिलाफ डेविस कप मुकाबले की मेजबानी की थी जिसमें मेजबान टीम 4–1 से जीत गई थी। वहीं कर्नाटक राज्य लॉन टेनिस संघ (केएसएलटीए) ने बिली जीन किंग कप प्ले–ऑफ की मेजबानी की थी। तब भारत ने सितंबर में विश्व ग्रुप एक के पहले दौर में स्विट्जरलैंड को हराकर क्वालीफाइंग चरण में प्रवेश किया था जबकि नीदरलैंड को दूसरे दौर में अर्जेंटीना के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। यह 1993 के बाद यूरोपीय धरती पर भारत की पहली जीत थी। तब सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश के नेतृत्व में भारत को जीत मिली थी।

आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2025: सिमरनप्रीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता, मनु भाकर पदक से चूकी

दोहा [क़तर] (एजेंसी)। भारतीय शूटर सिमरनप्रीत कौर ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबरी की। वहीं, ओलिंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर इस बार पदक जीतने में सफल नहीं रही।

सिमरनप्रीत की ऐतिहासिक जीत

21 वर्षीय सिमरनप्रीत ने फाइनल में 41/50 का स्कोर बनाते हुए विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उनका यह स्कोर दक्षिण कोरिया की पेरिस 2024 ओलिंपिक चैंपियन यांग जी-इन के जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर है। चीन की याओ चियान्शुन ने 36/50 के साथ सिल्वर मेडल और जर्मनी की डॉरेन वेनेकंप ने 30/45 के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह सिमरनप्रीत का द्बस्स्न्न वर्ल्ड कप फाइनल में पहला पदक है, जिससे वह विश्व की शीर्ष युवा शूटिंग प्रतिभाओं में शामिल हो गई हैं।

मनु भाकर का निराशाजनक प्रदर्शन

वहीं, मनु भाकर इस बार निराशा में रही। उन्होंने महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड में नौवां स्थान प्राप्त किया और फाइनल में जगह नहीं बना पाईं। इससे पहले, उन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पांचवां स्थान हासिल किया था, जिससे उनका दोहा अभियान बिना पदक के समाप्त हुआ।

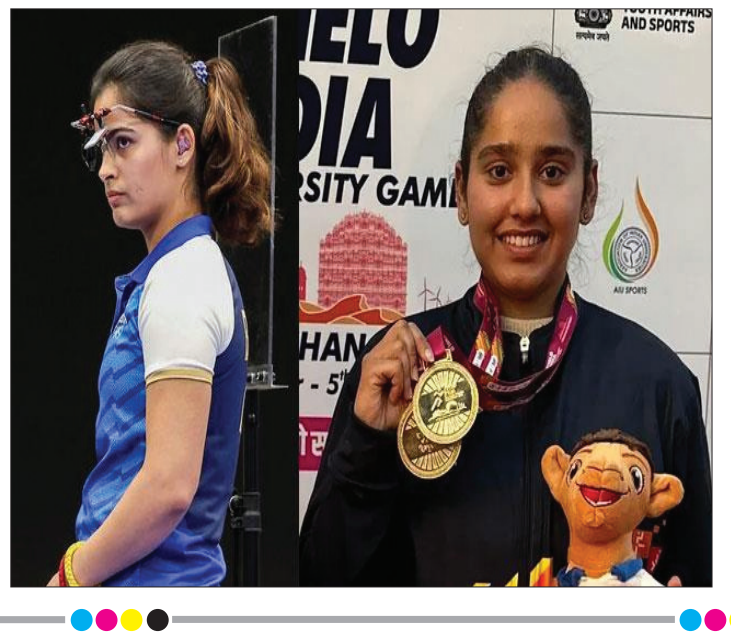

पुरुषों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का सिल्वर

पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इवेंट में ओलिंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने चेक शूटर जीरी प्रिव्रात्सकी के 414.2 वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर से केवल 0.9 अंकों से पिछड़कर यह पदक हासिल किया। चीन के पेरिस 2024 गोल्ड मेडलिस्ट लियू युकुन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल की विशेषताएं

दोहा मीट ने 2025 आईएसएसएफ सीज़न का समापन किया। इस फाइनल में कुल 10 शूटरों ने भाग लिया, जिनमें क्वालिफिकेशन के आधार पर चयनित खिलाड़ी शामिल हैं। डिफेंडिंग चैंपियन अपने आप क्वालीफाई होते हैं, जबकि चार वर्ल्ड कप स्टेज के विजेताओं को सीधे जगह मिलती है। शेष पांच स्थानों में दो खिलाड़ी वर्ल्ड कप रैंकिंग और तीन आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेताओं के आधार पर चुने गए। इस फाइनल में केवल व्यक्तिगत 12 ओलिंपिक शूटिंग इवेंट (राइफल, पिस्टल और शॉटगन) आयोजित किए गए, टीम इवेंट शामिल नहीं थे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

बल प्रयोग कर सकते हैं ट्रंप, कथित ड्रग तस्करी से जुड़ी नावों पर हमलों को लेकर बोले रक्षा मंत्री हेगसेथ

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कथित ड्रग कार्टेल से जुड़ी नावों पर सैन्य हमलों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास देश की सुरक्षा के लिए जैसा वह उचित समझें कार्रवाई करने का अधिकार है। हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप अपनी इच्छानुसार बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में बोलते हुए हेगसेथ ने हमलों की आलोचनाओं को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इन सैन्य हमलों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन हमलों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के संभावित उल्लंघन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीट हेगसेथ ने तर्क दिया कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन वाजिब था। उन्होंने इसकी तुलना 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद लिए गए फैसलों से की। हेगसेथ ने कहा कि अगर आप किसी घोषित आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और देश में नाव के जरिये ड्रग्स लाते हैं तो हम आपको ढूंढ लेंगे और डुबो देंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप देश के हितों की रक्षा के लिए जैसा सही समझेंगे, वैसी निर्णायक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं और करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश को इस पर शक नहीं होना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने संदिग्ध ड्रग तस्करों की तुलना आतंकवादी संगठन अल-कायदा से की। उनकी यह टिप्पणी ट्रंप प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करने के तुरंत बाद आई है, जिसमें यूरोपीय साझेदारों को कमजोर बताया गया है। इस रणनीति का मकसद अमेरिकी ताकत को पश्चिमी गोलार्ध में फिर से स्थापित करना है।

कंप के तेज झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता...दहशत में लोग

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के अलास्का राज्य और कनाडा के युकोन इलाके की सीमा पर शनिवार को एक ताकतवर 7.0 की तीव्रता वाला भूकंप आया। यह इलाका पहाड़ी है और यहां आबादी बहुत कम रहती है, इसलिए नुकसान की जानकारी अभी सीमित है। इस भूकंप के कुछ ही मिनट बाद 5.6 और 5.3 तीव्रता के दो और आफ्टरशॉक दर्ज किए गए। लगातार आने वाले झटकों से इलाके में दहशत का माहौल है। यह इलाका जंगलों, पहाड़ों और बर्फीले मैदानों से घिरा है, इसलिए यहां पहुंचना मुश्किल होता है। फिर भी अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। अमेरिकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने साफ किया है कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि झटके समुद्र के बहुत अंदर नहीं आए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की खबर नहीं है, लेकिन आफ्टरशॉक जारी रहने की वजह से लोग सावधानी बरत रहे हैं और स्थानीय एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

ड्रोन हमला : 33 बच्चों समेत 50 लोगों की मौत, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा

खार्तूम, एजेंसी। दक्षिण-मध्य सूडान में बच्चों के एक स्कूल पर एक अर्धसैनिक समूह द्वारा किये गये ड्रोन हमले में 33 बच्चों सहित 50 लोगों की मौत हो गई। चिकित्सकों के एक समूह ने यह जानकारी दी। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि दक्षिण कोर्डोफन प्रांत के कलोगी शहर में पैरामेडिक्स को 卐दूसरे अप्रत्याशित हमले卐 में निशाना बनाया गया। सूडान में नागरिकों के विरुद्ध हिंसा पर नजर रखने वाले एक अधिकार समूह, इमरजेंसी लॉयर्स ने शनिवार को एक बयान में बताया कि कलोगी में बचे लोगों का इलाज कर रहे पैरामेडिक्स पर दूसरा हमला हुआ है, तथा कहा कि 卐पिछले दो के निकट एक तीसरे नागरिक स्थल卐 पर भी हमला किया गया। समूह ने हमले की निंदा की तथा हमलों के लिए अर्धसैनिक समूह, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या आरएसएफ को दोषी ठहराया तथा इसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन बताया। मृतकों की संख्या अधिक होने की आशंका है, लेकिन इलाके में संचार व्यवस्था ठप होने के कारण हताहतों की सूचना देना मुश्किल हो गया है। बृहस्पतिवार को किया गया हमला अर्धसैनिक समूह 'रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) और सूडानी सेना के बीच जारी जंग में नया घटनाक्रम है। दोनों समूह दो साल से भी ज्यादा समय से युद्धरत हैं। अब युद्ध तेल-समृद्ध कोर्डोफन राज्य में केंद्रित है। सूडान में यूनिसेफ प्रतिनिधि शेल्डन येट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, स्कूल में बच्चों की हत्या बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संघर्ष की कीमत बच्चों को चुकानी पड़े। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ सभी पक्षों से ''इन हमलों को तुरंत रोकने और जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता की सुरक्षित व निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह करता है।

संपत्तियां फ्रीज, कंपनियों पर भी प्रतिबंध; खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ब्रिटेन की बहुत बड़ी कार्रवाई

लंदन, एजेंसी। भारत के दबाव के बीच ब्रिटेन ने खालिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्रिटिश सरकार ने 4 दिसंबर को गुरप्रीत सिंह रेहल नामक एक व्यक्ति और बब्बर अकाली लहर संगठन पर आतंकवाद से जुड़े आरोपों के तहत प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह कार्रवाई खासतौर पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन से इनकी सांठगांठ के लिए की गई है। इस कदम से ब्रिटेन की वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करने वाले चरमपंथियों को झटका लगेगा और भारत-ब्रिटेन के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। ब्रिटेन सरकार ने काउंटर-टेररिज्म (सैंक्शंस) (ईयू एग्जिट) रेगुलेशंस 2019 के तहत इन प्रतिबंधों को लागू किया है। मुख्य कार्रवाइयों में शामिल हैं- संपत्ति फ्रीज: रेहल, बब्बर अकाली लहर और इनसे जुड़ी कंपनियों की ब्रिटेन में स्थित सभी संपत्तियों, फंड्स और आर्थिक संसाधनों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है। ब्रिटिश नागरिकों या संस्थाओं को इन संसाधनों से कोई सौदा करने, या इन्हें कुछ भी उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं है, जब तक कि एचएम ट्रेजरी से लाइसेंस न मिले।

कंपनियों पर असर: रेहल से जुड़े संगठन सेविंग पंजाब सीआईसी, वाइटहॉक कंसल्टेशंस लिमिटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड संगठन लोहा डिजाइन्स पर भी प्रतिबंध लगे हैं। गुरप्रीत सिंह रेहल

को किसी कंपनी का निदेशक बनने या उसके प्रबंधन में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने से रोक दिया गया है। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर सात साल तक की कैद या 10 लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय के मूल्यांकन के अनुसार, यह पहली बार है जब घरेलू काउंटर-टेररिज्म रिजीम का इस्तेमाल खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के फंडिंग को बाधित करने के लिए किया गया है।

खालिस्तानी आतंक से जुड़े आरोप: भर्ती, फंडिंग और हथियार खरीद : गुरप्रीत सिंह रेहल पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों से जुड़ने का आरोप है। ब्रिटिश सरकार का मानना है कि वह बब्बर खालसा और बब्बर अकाली लहर की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इन आतंकी संगठनों की गतिविधियों में समूहों का प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन, भर्ती अभियान चलाना, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, हथियारों और अन्य सैन्य सामग्री की खरीद में सहायता और ऐसे ही संगठनों को समर्थन और सहयोग देना शामिल है। बब्बर अकाली लहर को बब्बर खालसा का सहयोगी संगठन माना जाता है, जो इसकी भर्ती, प्रचार और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, जो खालिस्तान आंदोलन के नाम पर हिंसा और घृणा फैलाने के लिए फेमस है। ब्रिटेन सरकार की ये कार्रवाइयां भारत में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने वाले नेटवर्क को निशाना बनाती है।

ब्रिटिश अधिकारियों के बयान: आतंकवाद के फंडिंग को कुचलेंगे : आर्थिक सचिव लूसी रिग्बी केसी एमपी ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि जब आतंकवादी ब्रिटेन की वित्तीय प्रणाली का शोषण करेंगे तो हम चुपचाप नहीं देखेंगे। यह ऐतिहासिक कदम दर्शाता है कि हम हर उपलब्ध टूल का इस्तेमाल करके आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए तैयार हैं- चाहे वह कहीं भी हो। ब्रिटेन उन शांतिपूर्ण समुदायों के साथ दृढ़ता से खड़ा है, जो हिंसा और घृणा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ हैं।

भारत-ब्रिटेन सहयोग को मिली मजबूती: वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा : यह कदम भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते आतंकवाद विरोधी सहयोग का प्रतीक है। ब्रिटेन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह विदेशी मिट्टी पर आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे खालिस्तानी चरमपंथियों के वैश्विक फंडिंग चैनलों पर असर पड़ेगा। इससे भारत की सुरक्षा चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं।

बब्बर खालसा का इतिहास और खतरा : बब्बर खालसा 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन के दौरान उभरा। यह भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। यह संगठन हथियार तस्करी, विस्फोटक हमले और राजनीतिक हत्याओं में लिप्त रहा है। ब्रिटेन में इसके समर्थक लंदन और अन्य शहरों में सक्रिय हैं, जहां वे फंडिंग और प्रचार के जरिए गतिविधियां चलाते हैं। हाल के वर्षों में, भारत ने ब्रिटेन से ऐसे नेटवर्क्स पर कार्रवाई की मांग की थी, और यह संयुक्त घोषणा उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कार्रवाई ब्रिटेन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो वैश्विक आतंकवाद को फंडिंग रोकने पर केंद्रित है। आने वाले दिनों में और प्रतिबंधों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ रहा है।

न्यू साउथ वेल्स के जंगल में आग लगने से 12 घर जलकर खाक

सिडनी, एजेंसी। आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जंगलों में आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गये हैं। आस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस ने पुष्टि की है कि आग से कई घर जलकर खाक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) ने शनिवार दोपहर यह जानकारी दी। एबीसी ने बताया कि घरों में आग लगने की घटना तक सामने आई जब नेटवर्क के न्यूज़ हेलीकॉप्टर से चलाए गए लाइव वीडियो में निंबिन रोड, कोलूवोंग के पास कम से कम 12 घर आग लगने से पूरी तरह खाक हो गये थे। न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस ने आज दोपहर निंबिन रोड के लिए एक आपातकालीन चेतावनी जारी की। जंगल में लगी आग दक्षिण दिशा के ग्लेनरॉक परेड से लारा स्ट्रीट की ओर बढ़ रही है। अधिकारियों ने आग में फंसे लोगों से कहा, अगर आप निंबिन रोड, ग्लेनरॉक परेड, लारा स्ट्रीट और निमाला एवेन्यू के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए खतरा हैं। यदि रास्ता साफ मिलता है तो अभी वॉय वॉय की ओर सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। कोलूवोंग न्यू साउथ वेल्स के सेंट्रल कोस्ट का

एक उपनगर है, जो सिडनी सीबीडी से लगभग एक घंटे की दूरी पर स्थित है। एबीसी ने यह भी रिपोर्ट दी है कि कोलूवोंग में पटरियों के पास आग लगने के कारण सेंट्रल कोस्ट और न्युकैसल रेलवे लाइन पर ट्रेनों को आवागमन नहीं हो रहा है। एनएसडब्ल्यू आरएफएस ने बाद में बैरामी, बैरामी क्रीक, विडन, यारावा और केराबी क्षेत्रों के लिए एक और आपातकालीन चेतावनी जारी की, क्योंकि वहां जंगल के एक बड़े क्षेत्र में जबरदस्त आग लगी है। ये क्षेत्र एनएसडब्ल्यू के ऊपर क्षेत्र में हैं और सिडनी सीबीडी से 200 किलोमीटर से अधिक उत्तर-पश्चिम में स्थित हैं। अधिकारियों ने इन क्षेत्रों के लोगों को सूचित किया कि उनकी जान खतरे में हैं और अब इलाके से बाहर निकलने में बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने लोगों से एक मजबूत संरचना के अंदर शरण लेने का आग्रह किया है।

चीनी सैन्य विमान ने जापानी विमानों पर दो बार लॉक किया रडार, जापान ने दर्ज कराया कड़ा विरोध; तनाव बढ़ा

टोक्यो , एजेंसी। चीन के एक सैन्य विमान ने शनिवार (स्थानीय समयानुसार) को ओकिनावा के पास जापानी लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक किया। जापान ने आज इस घटना को लेकर चीन के सामने विरोध दर्ज कराया है। चीनी सैन्य विमान ने विमानवाहक पोत लियानओनिंग से उड़ान भरी थी। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री के ताइवान पर दिए बयान के बाद दोनों देशों के संबंध खराब हो गए हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, लियाओनिंग से उड़ान भरने वाले जे-15 लड़ाकू विमान ने शनिवार को दो बार जापान के एफ-15 विमानों पर अपना रडार लॉक किया। पहली बार देर दोपहर करीब तीन मिनट के लिए और दूसरी बार शाम में लगभग 30 मिनट तक रडार लॉक किया गया। हालांकि जापान के हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और न ही किसी तरह का नुकसान हुआ। रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने इसे बेहद खतरनाक हरकत बताया। उन्होंने कहा कि चीन का यह कदम सुरक्षित सैन्य उड़ान संचालन की सीमा से बाहर है। उन्होंने कहा कि जापान ने चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। चीन पहले ही जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची के उस बयान पर नाराजगी जता चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर कोई कार्रवाई करता है तो जापान भी इसमें शामिल हो सकता है। घटना के दौरान लियाओनिंग ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच से गुजर रहा था और वह प्रशांत महासागर में विमान संचालन का अभ्यास कर रहा था। जापानी एफ-15 विमान सतर्कता के तौर पर हवा में भेजे गए थे और वे सुरक्षित दूरी पर रहते हुए चीनी विमानों पर नजर रख रहे थे। रक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि लड़ाकू विमान रडार का इस्तेमाल सामान्य खोज के लिए भी करते हैं और मिसाइल दागने से पहले फायर कंट्रोल के रूप में भी। माना जा रहा है कि जापान और चीन के बीच रडार लॉक की यह पहली घटना है। इससे पहले साल 2013 में एक चीनी युद्धपोत ने जापानी डेस्ट्रॉयर पर रडार लॉक किया था।

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत नाजुक, लंदन रवाना होने की तैयारी फिर टली

ढाका , एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और तीन बार देश का नेतृत्व कर चुकीं खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लंदन ले जाने की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने एक बार फिर उनकी यात्रा टाल दी है। शनिवार को मेडिकल बोर्ड ने साफ कहा कि इस समय खालिदा जिया का विदेश जाना सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से लंदन रवाना करने की योजना अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक, खालिदा जिया को फिलहाल ढाका के एवरकेयर अस्पताल के CCU में रखा गया है। 80 साल की जिया को पिछले महीने सीने में गंभीर संक्रमण होने के बाद भर्ती कराया गया था। उनकी हालत लगातार उठ-बैठ रही है, इसलिए मेडिकल बोर्ड ने यात्रा को 'जोखिम भरा' बताया। डॉक्टरों का कहना है कि एयर

एम्बुलेंस तैयार है, लेकिन मरीज की स्थिति यात्रा योग्य होने पर ही उड़ान होगी। पहले तय था कि जिया शुक्रवार को लंदन रवाना होंगी, लेकिन कतर की ओर से भेजी जा रही एयर एम्बुलेंस तकनीकी खराबी के कारण ढाका नहीं पहुंच सकी। बाद में मीडिया रिपोर्ट में दावा हुआ कि कतर ने जर्मनी से दूसरा विमान मंगवाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि मरीज की हालत अब यात्रा की अनुमति नहीं देती। BNP नेता डॉक्टर जाहिद हुसैन ने बताया कि जिया की विदेश यात्रा उनकी सेहत सुधरते ही कराई जाएगी।

बेटे तारीक की पत्नी ढाका पहुंचीं : खालिदा जिया के बेटे और BNP के कार्यवाहक प्रमुख तारीक रहमान लंदन में रहते हैं और कई कानूनी कारणों से बांग्लादेश नहीं लौट पा रहे। हालांकि उनकी पत्नी जुबैदा रहमान शुक्रवार को ढाका पहुंच गईं ताकि जिया को लंदन ले जाने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकें। तारीक रहमान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे मां के पास आना चाहते हैं, लेकिन यह निर्णय सिर्फ उनके हाथों में नहीं है।

हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी तैयारी : जिया की हालत बिगड़ने के बाद सेना और वायुसेना ने एवरकेयर अस्पताल की छत पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग ट्रायल भी किया था। योजना यह थी कि जरूरत पड़ने पर सीधे अस्पताल से उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। इससे साफ होता है कि सरकार और चिकित्सा बोर्ड पूरी प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से संभाल रहे हैं। क्ककक नेता देशभर में मस्जिदों और मंदिरों में जिया के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक स्थिति के बीच क्ककक पहले ही मुख्य राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर चुकी है। अब खालिदा जिया की खराब सेहत ने पार्टी के भविष्य को और संवेदनशील बना दिया है।

ताइवान के करीब चीन ने बढ़ाई सैन्य गतिविधियां, गश्त करते दिखे दो विमान और सात नौसैनिक जहाज

ताइपे , एजेंसी। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) ने रविवार को बताया कि उसके क्षेत्र के आस-पास चीनी सेना (पीएलए) के दो विमान उड़ान भरते हुए और सात नौसैनिक (पीएलएएन) जहाज गतिविधि करते हुए दिखाई दिए। इसी समय एक चीनी गुब्बारा भी देखा गया। मंत्रालय ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा, आज सुबह छह बजे (स्थानीय समयानुसार) तक ताइवान के आसपास पीएलए के दो विमानों और पीएलएएन के सात जहाजों की गतिविधि दर्ज की गई। इसी समय एक चीनी गुब्बारा भी पाया गया। ताइवान के रक्ष बलों ने स्थिति की निगरानी और प्रतिक्रिया दी। शनिवार को ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियां बढ़

गईं। उस दिन चीन के 29 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और छह नौसैनिक जहाजों की गतिविधि देखी गई। इस बीच, जो बाइडन प्रशासन के पूर्व रक्षा अधिकारी एलि रैटनर ने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बयान को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि ताइवान की रक्षा में जापान के शामिल होने की संभावना पर चीन की प्रतिक्रिया अनुचित है। ताइपे टाइम्स के मुताबिक, एलि रैटनर 2021 से इस वर्ष तक हिंद-प्रशांत सुरक्षा मामलों के लिए सहायक रक्षा सचिव थे। उन्होंने कहा कि ताइवान पर टिप्पणी कर ताकाइची ने केवल जापान की आधिकारिक नीति दोहराई है। सात नवंबर को जापानी प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो इसे जापान के अस्तित्व के लिए खतरा माना जा सकता है और जापान को कदम उठाना पड़ सकता है। ताकाइची दशकों में पहली जापानी नेता हैं, जिन्होंने खुलकर कहा कि ताइवान जलडमरूमध्य में संकट के समय जापान की सेना शामिल हो सकती है। उनके बयान से चीन नाराज हुआ और उसने जापान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें जापान की यात्रा और शिक्षा पर चेतावनी और जापानी समुद्री भोजन के आयात को रोकना शामिल है।

संदिग्ध गुब्बारों से हड़कंप, लिथुआनिया का विलनियस एयरपोर्ट बंद

लिथुआनिया , एजेंसी। लिथुआनिया के विलनियस एयरपोर्ट ने शनिवार को अपने सभी ऑपरेशंस रोक दिए। वजह थी एयरपोर्ट के ऊपर अचानक कुछ गुब्बारे दिखाई देना। देश की नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर ने बताया कि एयर ट्रैफिक 1905 तस्र्ल्ज्ञ तक बंद रहेगा। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। विलनियस एयरपोर्ट, जो बेलारूस की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, अक्टूबर की शुरुआत से अब तक 10 से ज्यादा बार इसी वजह से बंद किया जा चुका है। आखिरी बार एयरपोर्ट 3 दिसंबर को बंद किया गया था।

गुब्बारे कौन भेज रहा है : लिथुआनिया का कहना है कि ये गुब्बारे बेलारूस से तस्करों द्वारा भेजे जा रहे हैं, जो इनके जरिये सिगरेट की तस्करी करते हैं। लेकिन बात सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं है, लिथुआनिया बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर भी उंगली उठा रहा है। लिथुआनिया का आरोप है कि बेलारूस की सरकार इन्हें रोक नहीं रही बल्कि यह एक तरह का ÷हाइब्रिड अटैक÷ है, जिससे लिथुआनिया के हवाई यातायात को बाधित किया जा रहा है। लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी हैं, इसलिए ये घटनाएं राजनीतिक तौर पर भी संदेह पैदा करती हैं

हाइब्रिड अटैक क्या होता है : जब किसी देश को सीधे हमला किए बिना असामान्य तरीकों से तनाव पैदा किया जाए। आर्थिक या सुरक्षा व्यवस्था को बाधित किया जाए तो इसे हाइब्रिड अटैक कहा जाता है। लिथुआनिया का कहना है कि गुब्बारों को लगातार भेजकर एयरपोर्ट को बंद करने की नौबत खड़ी की जा रही है, जिससे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है।

एयरपोर्ट बंद होने का असर : बार-बार एयरपोर्ट बंद होने से फ्लाइटें देरी से उड़ रही हैं या कैंसल हो रही हैं। यात्रियों को असुविधा हो रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ रही है कि यह सिलसिला कहां तक जाएगा। सरकारी एजेंसियां अब लगातार एयरस्पेस की निगरानी कर रही हैं, ताकि गुब्बारों के कारण फिर से एयरपोर्ट को बंद न करना पड़े।

पुतिन की भारत यात्रा ट्रंप की नाकामी, पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बड़ा बयान; अमेरिकी नीति को बताया पाखंड

वॉशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को बहुसंख्य अमेरिकी नागरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोर नाकामी के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी नागरिक ट्रंप को पसंद नहीं करते। रूबिन ने दावा किया कि हालिया सर्वे में पाया गया है कि अमेरिका के 65 प्रतिशत लोग ट्रंप को नापसंद करते हैं। अमेरिकी पूर्व अधिकारी ने कहा कि रूस से रियायती तेल खरीदने पर भारत को लेक्चर देकर अमेरिका पाखंड कर रहा है क्योंकि वॉशिंगटन खुद मॉस्को के साथ व्यापार में शामिल है। उन्होंने नई दिल्ली की अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने की स्थिति को सही ठहराया। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने अमेरिका की कड़ी आलोचना तब की जब उनसे नई दिल्ली दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उस

टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि मॉस्को बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और उसकी अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं। उन्होंने अगस्त में भारतीय आयात पर अमेरिका की तरफ से 50त्न टैरिफ लगाने की आलोचना की। वाशिंगटन का दावा है कि यह तेल यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध प्रयासों को बढ़ावा देता है।

रूसी तेल खरीद पर अमेरिका कर रहा पाखंड : रूबिन ने खास बातचीत में कहा, जो बात अमेरिकियों को समझ नहीं आती, वह यह है कि भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। अमेरिका पाखंड कर रहा है क्योंकि हम रूस से खरीदते हैं। हम ऐसे सामान और मटीरियल खरीदते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई दूसरा बाजार नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हम नहीं चाहते कि भारत रूसी तेल खरीदे तो हमें भारत को सस्ती कीमत पर और जितनी मात्रा में उसे जरूरत है उतनी मात्रा में ईंधन देने के लिए हम क्या करने वाले हैं।

पाकिस्तान को गले लगाने पर भी सवाल : पूर्व पेंटागन अधिकारी ने पाकिस्तान को गले लगाने के लिए अमेरिका के पास कोई रणनीतिक तर्क नहीं होने का दावा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने जून में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस दौरे पर भी आपत्ति जताई और कहा कि मुनीर को अमेरिका में गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

राहुल गांधी मानहानि केस- परिवादी की गवाही दर्ज, आज भी होगी जिरह

सुलतानपुर (एजेंसी)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि प्रकरण में लोकसभा में नेतापक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में सोमवार को परिवादी के गवाह की गवाही दर्ज की गई। परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार गवाह रामचंद्र दूबे अदालत में उपस्थित हुए, जिनकी मुख्य गवाही दर्ज की गई।

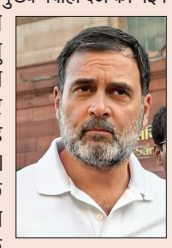

इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने गवाह से जिरह शुरू की, किंतु जिरह पूर्ण न होने पर अदालत ने शेष जिरह के लिए कल नौ दिसंबर की तारीख तय की है। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2018 का है। चार अगस्त को कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि वाद दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक जनसभा में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर परिवादी ने अदालत शरण ली। कोर्ट ने मामले में 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था। राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को पेश होकर जमानत कराई थी। बाद में 25 जुलाई को उनका बयान दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने इस मुकदमे को राजनीतिक साजिश बताया था। अब गवाह रामचंद्र दूबे से बचाव पक्ष की शेष जिरह पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

पालघर पुलिस स्टेशन में महिला से दुष्कर्म, आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार

पालघर (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में कासा पुलिस स्टेशन के एक 40 वर्षीय कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। घटना पिछले सप्ताह थाने में तब हुई जब पीड़िता को बयान दर्ज कराने के बहाने बुलाया गया था। पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार, कांस्टेबल ने थाने में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले के सामने आते ही पुलिस विभाग ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कासा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को भी इस मामले के बाद ट्रांसफर कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं।

गिर सोमनाथ में भूकंप के हल्के झटके, किसी नुकसान की खबर नहीं

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमवार सुबह 10:51 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 दर्ज की गई। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने बताया कि अब तक कहीं से किसी प्रकार के नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार भूकंप का केंद्र गिर सोमनाथ क्षेत्र के निकट था। झटके महसूस होने के कारण लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर नहीं निकल आए। फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुक्सान की कोई सूचना नहीं है। फिर भी प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भूकंप के झटके और खतरे को लेकर भू-विज्ञान विशेषज्ञों का कहना है कि 3.1 तीव्रता के झटके सामान्य माने जाते हैं और इनमें गंभीर नुकसान की संभावना बेहद कम होती है। इसके बावजूद संबंधित विभाग सतर्कता के साथ सभी पहलुओं की निगरानी कर रहे हैं।

ऑल वेदर रोड के खिलाफ उतरा संघ... 7 हजार देवदार के पेड़ों को काटने का विरोध

उत्तरकाशी (एजेंसी)। उत्तराखंड में केन्द्र और राज्य सरकार की महत्वकांक्षी गंगोत्री हाईवे परियोजना यानी ऑल वेदर रोड के खिलाफ संघ यानी आरएसएस खुलकर विरोध में आ गया है। संघ के सह-सरकार्यवाह डॉ कृष्ण गोपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने परियोजना के तहत 7 हजार देवदार के पेड़ों को काटने का विरोध किया है। इसके बाद उत्तरकाशी के हर्षिल में 100 से ज्यादा लोगों ने देवदार के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा। इसका समर्थन देने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी पहुंचे। पर्यावरण जानकार ने बताया कि ये पेड़ भागीरथी इकोनॉमिक सेंसेटिव जोन में काटे जाएंगे, जिससे गंगा का पानी सूख जाएगा। इसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा और बर्फबारी में कमी होगी। इसी साल नवंबर में उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसार, ऑल वेदर रोड के कारण 41.92 हेक्टेयर वन क्षेत्र का नुकसान होगा, इसमें कई देवदार के पेड़ भी शामिल हैं। इससे पहले बताया गया था कि 900 किलोमीटर लंबी परियोजना में कुल 56 हजार से ज्यादा पेड़ काटे होने थे, जिनमें से लगभग 36,000 पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे।

प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते 34 मछुआरे गिरफ्तार, दो नौकाएं भी जब्त

कोच्ची (एजेंसी)। ओडिशा के वन अधिकारियों ने केंद्रपाड़ा जिले के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य से 34 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और दो नौकाएं भी जब्त किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ये गिरफ्तारियां पिछले 48 घंटों में की गईं। आरोप है कि मछुआरे प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। भितरकनिका के सहायक वन संरक्षक ने बताया कि अभयारण्य के निषिद्ध क्षेत्रों में पहुंचे मछुआरों की नौकाएं वन गश्ती दलों ने जब्त कर ली हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मछुआरे बालासोर और मयूरभंज जिलों के निवासी हैं। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नौकाएं अभयारण्य के प्रतिबंधित गलियारों तक घुस आईं और उन्होंने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ओडिशा समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम और समुद्री अभयारण्य से जुड़े अनिवार्य नियमों का उल्लंघन किया। ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के प्रजनन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के आरोप में अब तक करीब 200 मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें राज्य सरकार ने लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए एक नवंबर से धामरा से देवी नदी के मुहाने तक 20 किलोमीटर के इलाके में सात महीने के लिए मछली पकड़ने पर बैन लगा दिया है। हालांकि, गहिरमाथा को समुद्री अभयारण्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण यहां यह प्रतिबंध पूरे साल लागू रहता है।

अच्छे कानून बनाने के लिए सांसद व्हिप से मुक्त हो, कांग्रेस नेता तिवारी ने पेश किया निजी बिल

भविष्य में वे सांसद पार्टी लाइन से हटकर वोट कर सकें

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सांसदों को व्हिप की बाध्यता को कम करने के लिए लोकसभा में एक निजी बिल पेश किया है। इसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को व्हिप से मुक्त करे, ताकि भविष्य वे पार्टी लाइन से हटकर भी सांसद वोट कर सकें।

शुक्रवार को दलबदल रोधी कानून में संशोधन के लिए गैर-सरकार विधेयक पेश करने वाले कांग्रेस नेता तिवारी ने कहा कि बदलाव से सांसद जनता की आवाज के मुताबिक फैसला होगा, न कि सिर्फ पार्टी आदेशों के मुताबिक होगा। कांग्रेस नेता तिवारी ने कहा कि इसका इरादा अच्छे कानून बनाना और लोकतंत्र में सांसदों की आजाद राय सुनिश्चित करना है। ताकि वे पार्टी लाइन का पालन किए बिना अपने विवेक से किसी भी बिल-प्रस्ताव पर वोट करने या न करने का फैसला ले सकें।

फिलहाल यदि सांसद पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करते हैं, तब उनकी सदस्यता खतरे में आ जाती है, लेकिन बिल से सांसदों की सदस्यता सिर्फ तभी खत्म होगी, जब वे विश्वास-अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मनी बिल या वित्तीय मामलों पर पार्टी निर्देश के खिलाफ वोट दें या अनुपस्थित रहें। किसी बिल या प्रस्ताव पर जारी पार्टी निर्देश की जानकारी हाउस के चेयरमैन या स्पीकर सदन में घोषित करते है। यदि कोई सदस्य निर्देश के खिलाफ जाता है, तब सदस्यता स्वतः समाप्त होगी। सदस्य को 15 दिनों के भीतर स्पीकर/चेयरमैन के पास अपील करने का अधिकार होगा और अपील का निपटारा 60 दिनों में होना चाहिए। कांग्रेस सांसद तिवारी ने कहा कि संसद में कई बार कोरम पूरा नहीं होता और लॉमेकिंग में सांसदों की भूमिका सीमित हो गई है। कानून मंत्रालय में तैयार होते हैं, मंत्री तैयार बयान पढ़ते हैं और व्हिप के कारण ट्रेजरी और विपक्ष दोनों तयशुदा लाइन पर वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि 1950 से 1985 तक व्हिप लगाए जाते थे, लेकिन वे बाध्यकारी नहीं थे। 1967 में 'आया राम गया राम' की घटनाओं के बाद दलबदल बढ़ा और आखिर में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 10वां शेड्यूल लागू किया।

पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर... अब पार्टी की कमान संभालें निशांत

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। राजधानी पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं, जिन पर लिखा है, अब पार्टी की कमान संभालें निशांत और नीतीश सेवक मांगें निशांत। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी निशांत के राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी सदस्य और समर्थक चाहते हैं कि निशांत पार्टी में शामिल हों, लेकिन अंतिम फैसला निशांत को ही लेना है। राजधानी पटना में ये पोस्टर तब समय पर सामने आए हैं जब जदयू ने राज्य में 2025 से 2028 तक के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। बात दें कि निशांत कुमार नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। उन्होंने सेंट केरन्स (पटना), मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल (मसूरी) और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटीआई) मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है। 2017 में उन्होंने राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं होने की बात कही थी और कहा था कि उनका पहला प्यार आध्यात्म है। हालांकि, इस साल जनवरी में वह बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में नजर आए थे और पिता के लिए समर्थन जुटा रहे थे। यह घटनाक्रम दिखाता है कि जदयू के भीतर और समर्थकों के बीच निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग बढ़ रही है।

मस्जिद की नींव हुमायूं ने नहीं, ममता बनर्जी ने रखी... वह ड्रामा कर रही

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का टीएमसी पर आरोप

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठा दिए हैं। भाजपा के आरोप हैं कि सीएम ममता अपने नेताओं और सांसदों से ही इसके खिलाफ बयान दिला रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में मस्जिद की नींव रखी थी।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हुमायूं ने नहीं, ममता बनर्जी ने नींव रखी हैं, और वह ड्रामा कर रही हैं और अपने नेताओं और सांसदों से इसके खिलाफ बयान दिलवा रही हैं। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा, ममता बंगाल की धरती को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरी जगह हो रहा है। ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।

केंद्रीय मंत्री सिंह ने संसद में होने वाली चर्चा पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, अगर भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में वंदे मातरम् पर चर्चा नहीं होगी, तब कहां होगी? वंदे मातरम् अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का यह गीत बंगाल की धरती से था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह भारत की विरासत है...।

रिपोर्ट्स के अनुसार, टीएमसी से निलंबित होने के बाद अब कबीर नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर वह 22 दिसंबर को बड़ी घोषणा कर सकते हैं। खबरें थीं कि मस्जिद की नींव रखने के प्रस्ताव के बाद से ही सीएम बनर्जी विधायक से नाराज थीं। हालांकि, पार्टी ने इस लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

तमिलनाडु में 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के कट सकते हैं नाम, 11 दिसंबर तक जमा होंगे फार्म

-मध्यप्रदेश में 14.88 लाख ऐसे वोटर जिनके नाम 2003 की लिस्ट से नहीं हो मैच

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के फॉर्म 11 दिसंबर तक जमा होंगे। इस बीच तमिलनाडु में अब तक मिले डेटा से पता चलता है कि मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। राज्य में अब तक 84.91 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म अनकलेक्टेबल श्रेणी में हैं यानी इन फॉर्म को अलग-अलग कारणों से इकट्ठा नहीं किया सकता है। इसमें अधूरी जानकारी होना, 2003 की लिस्ट में नाम न मिलना, वोटर की मौत या शिफ्ट हो जाना प्रमुख कारण हैं।

वहीं बंगाल में शुक्रवार तक अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या 54.59 लाख थी यानी इनके नाम वोटर्स लिस्ट से कटने की आशंका है, जबकि केरल में जिन वोटरों का पता नहीं चल रहा है, जो मर चुके हैं या स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं। उनकी संख्या बढ़कर 20 लाख से ज्यादा हो गई है।

दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा।

तमिलनाडु में 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची से इन नामों को हटाया जा सकता है। यह आंकड़ा राज्य के कुल 6.41 करोड़ मतदाताओं का 13.24फीसदी है। इसमें 44.22 लाख फॉर्म हमेशा के लिए शिफ्ट श्रेणी में हैं। वहीं 26.18 लाख को मृत, 10.73 लाख को अनुपस्थित और 3.5 लाख को डुप्लीकेट श्रेणी में रखा गया है। हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि प्रक्रिया अभी चल रही है। ये डेटा फाइनल नहीं है। केरल में अनकलेक्टेबल की लिस्ट में 20.75 लाख लोग हैं। इसमें से 7.39 लाख स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं। 6.11 लाख फॉर्म ऐसे लोगों के हैं, जो मर चुके हैं। वहीं 5.66 लाख का पता नहीं चला है। 1.12 लाख नाम डुप्लीकेट हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 23.71 लाख डेथ वोटर्स, 10.25 लाख लापता, 19.08 लाख शिफ्टेड और 1.26 लाख डुप्लीकेट वोटर्स शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में 14.88 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं, जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो रहे। इनका कोई लिंक न तो ब्लड रिलेशन से मिल रहा है और न ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। ऐसे वोटरों के नाम कटना तय माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग के अफसरों ने सभी जिला प्रशासन को नो-मैपिंग वाले वोटरों की क्रॉस-चेकिंग करने की हिदायत दी है, ताकि नोटिस जारी करने में कोई समस्या न आए।

चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को एसआईआर की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने-हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं, पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

सिद्दारमैया को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: चुनावी वादों पर भ्रष्ट आचरण का आरोप

-चुनाव लड़ने से रोकने की मांग

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को सुप्रीम कोर्ट ने वरुणा सीट से उनके 2023 के चुनाव के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका वरुणा क्षेत्र के मतदाता शंकरा ने दायर की है, जिसमें निम्नलिखित की मांग की गई है कि सिद्दारमैया का चुनाव रद्द किया जाए। उन्हें अगले छह साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाए।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में जो पांच वादे किए थे, वे मतदाताओं को रिश्वत देने के समान हैं। यह घोषणापत्र सिद्दारमैया की सहमति से जारी हुआ था, इसलिए उन पर भ्रष्ट आचरण का मामला बनता है। इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने इन वादों को भ्रष्ट आचरण बताकर कहा है कि इनसे पुरुषों के साथ भेदभाव हुआ, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपए प्रतिमाह, प्रत्येक बीपीएल परिवार के सदस्य को 10 किलो अनाज प्रतिमाह, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल तक 3,000 रुपए प्रतिमाह, डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए प्रतिमाह और राज्य में सभी महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अप्रैल में याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि चुनाव में किए गए वादे करप्ट प्रैक्टिस (भ्रष्ट आचरण) की श्रेणी में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच) ने शुरुआत में बेंच ने याचिका खारिज करने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि, अदालत को तमिलनाडु के लंबित मामले (एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार, 2013) की जानकारी दी गई, जिसमें समान चुनावी वादों को भ्रष्ट आचरण माना जाए या नहीं, इस पर तीन न्यायाधीशों की बेंच के सामने चुनौती लंबित है। इसी कारण, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी सुनवाई की अनुमति दी और सिद्दारमैया तथा अन्य पक्षों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। यह मामला भारतीय राजनीति और चुनावी नियमों के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को कानूनी रूप से भ्रष्ट प्रैक्टिस माना जा सकता है या नहीं।

बीकानेर बार्डर पार करने की कोशिश कर रहे छात्र को सुरक्षाबलों ने पकड़ा, जासूसी का शक

-पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहती है प्रेमिका, 2017 में जेल में हुई थी मुलाकात

बीकानेर (एजेंसी)। राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला सेक्टर में सुरक्षाबलों ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हुए आंध्र प्रदेश के एक बीटेक ग्रेजुएट छात्र को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम प्रशांत वेदम है, जो विशाखापट्टनम का रहने वाला है। उसने सुरक्षा एजेंसियों को बताया कि वह पाकिस्तान में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। वह एक बार पहले भी बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जा चुका है।

मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि प्रशांत वेदम शुक्रवार दोपहर को खाजूवाला में एक बस से उतरा और इंटरनेशनल बॉर्डर की चला गया, तभी आर्मी कैंप के चक 17 के पास सैनिकों को उसका व्यवहार संदिग्ध लगा और उन्होंने उसे रोक लिया। थोड़ी देर पूछताछ के बाद उन्होंने उसे खाजूवाला पुलिस को सौंप दिया। खाजूवाला एसएचओ के मुताबिक प्रशांत वेदम खुलेआम पाकिस्तान जाने की बात कर रहा था और सीमा पार करने का आसान रास्ता ढूंढ रहा था। आर्मी इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी मिली और उसे तुरंत पकड़ लिया। जांच अधिकारियों को शक है कि वह पाकिस्तान लौटने की कोशिश कर रहा था, उसके पाकिस्तान जाने का असली मकसद पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। एसएचओ ने कहा कि अब उससे आर्मी और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी।

रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि यह प्रशांत वेदम की पहली कोशिश नहीं थी। वह पहले 2017 में बीकानेर में करणी पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान गया था। उस समय उसे पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था और वह 2021 तक उनकी हिरासत में रहा था, जिसके बाद उसे अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत भेज दिया गया। दोबारा यात्रा करने की उसकी कोशिश ने उसके बयान पर शक पैदा कर दिया है और आर्मी को भी उसके दावों पर शक है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ ने बताया कि वह दावा कर रहा है कि उसे पाकिस्तान में एक महिला से प्यार हो गया था जिसे वह अपनी गर्लफ्रेंड प्रविता बता रहा है जो दूसरी सेल में जेल में थी जो रावलपिंडी में रहती है। प्रशांत ने पुलिस को बताया है कि वह उससे मिलने के लिए पाकिस्तान वापस जा रहा था। यह साफ नहीं है कि वह अभी भी उस लड़की के संपर्क में था या नहीं। अधिकारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश में प्रशांत के परिवार को सूचना दे दी गई है और उसका भाई अधिकारियों की मदद के लिए खाजूवाला आने के लिए निकल गया है। उसके भाई ने बताया कि प्रशांत वेदम को कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्या है।

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत बीटेक ग्रेजुएट है। वह चीन और अफ्रीका में भी काम कर चुका है। पुलिस ने बताया कि प्रशांत को अब खाजूवाला में सेफ हाउस में रखा गया है, जहां अलग-अलग खुफिया एजेंसियां उससे मिलकर पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता चल सके कि यह सीमा पार जासूसी का मामला तो नहीं है।

इंडिगो संकट... क्या डीजीसीए के फरमान के बाद भी लापरवाह बना रहा कंपनी का हाई-प्रोफाइल बोर्ड

-कंपनी की आंतरिक निगरानी प्रणाली की क्षमता पर भी प्रश्नचिह्न लगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बीते पांच दिनों से गंभीर परिचालन संकट में है, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। उड़ानों के लगातार रद्द और विलंब होने से एयरपोर्ट्स पर अराजकता का माहौल बना हुआ है। इस घटना ने न केवल इंडिगो के संचालन मॉडल पर सवाल उठा दिए हैं, बल्कि कंपनी के हाई-प्रोफाइल बोर्ड और उसकी आंतरिक निगरानी प्रणाली की क्षमता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिगो प्रबंधन और बोर्ड ने संकट की आशंका को देखकर कोई ठोस रणनीति बनाई गई थी।

मामले के केंद्र में पायलटों के लिए लागू होने वाले फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम हैं, जिन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जनवरी 2024 में अधिसूचित किया था। शुरुआत में यह नियम 1 जून 2024 से लागू होने थे, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों के विरोध के चलते इन्हें बाद में दो चरणों में 1 जुलाई और 1 नवंबर 2025 से लागू करने का फैसला हुआ। इसके बावजूद, इंडिगो इन्हें लागू करने की तैयारी समय रहते नहीं कर सकी, इसके परिणामस्वरूप पायलटों की कमी और ड्यूटी शेड्यूल में अव्यवस्था पैदा हुई और संचालन चरमरा गया।

रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो के बोर्ड में कई जानी-मानी हस्तियां हैं, लेकिन उनके बावजूद ऐसी चूक होना हैरान करने वाला है। बोर्ड में इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और एयरलाइन के सह-संस्थापक राहुल भाटिया, पूर्व जी20 शेरपा अमिताभ कांत, सेबी के पूर्व चेयरमैन दामोदरन, पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की मैनेजिंग पार्टनर पल्लवी श्रॉफ, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस के पूर्व वकील माइक व्हिटेकर और चेयरमैन विक्रम मेहता जैसे नाम शामिल हैं। इसके बावजूद, तैयारी में कमी उजागर होने से बोर्ड की जवाबदेही पर तीखी आलोचना हो रही है।

वहीं डीजीसीए पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नियामक समय रहते स्थिति को भांप सका था। हालांकि डीजीसीए ने कहा है कि उसने तैयारी पूरी करने के लिए एयरलाइन को लगातार चेतावनी और निर्देश दिए थे। यह पूरा मामला न केवल प्रबंधन क्षमता, बल्कि भारत की विमानन नियामक व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी गंभीर बहस छेड़ चुका है। यात्रियों की असुविधा का सिलसिला जारी है और अब सभी की निगाहें इंडिगो की सुधारात्मक कार्रवाई पर टिकी हैं।